हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 227 बेमेतरा, शनिवार 11 अप्रैल 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

त्रिपुरा में होने वाले एडीसी चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा बलों की 24 कंपनियां तैनात

अगस्तला। त्रिपुरा में रविवार को होने वाले स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) चुनावों के मद्देनजर पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनावों के लिए प्रचार अभियान शुक्रवार शाम को थम जायेगा। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 24 कंपनियां (लगभग 2,400 जवान) को तैनात किया गया है। असम में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद ये जवान त्रिपुरा पहुंच रहे हैं। इनमें से चार कंपनियां पहले ही पहुंच चुकी हैं और आज रात तक सभी की तैनाती हो जाएगी। सुरक्षा बलों में सीएपीएफ की 12 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 12 कंपनियां और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 10 कंपनियां शामिल हैं। ये जवान मुख्य रूप से संवेदनशील और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे।

नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली

नयी दिल्ली। बिहार से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्य नीतीश कुमार ने शुक्रवार को संसद भवन में सदन की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने जनता दल यू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शपथ दिलाई। कुमार ने हिंदी भाषा में शपथ ली। वह राज्यसभा के लिए हाल ही में हुए द्विवार्षिक चुनाव में उच्च सदन के लिए चुने गये थे। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा , विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद जयराम रमेश, राजीव शुक्ला, संजय कुमार झा, राजीव प्रताप रूडी, राज्यसभा के महासचिव पी. सी. मोदी और राज्यसभा सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शेयर बाजारों में शुरुआती तेजी, 600 अंक से ज्यादा उछला सेंसेक्स

मुंबई। विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को शुरुआती बढ़त देखी गयी और बीएसई का सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा उछल गया। अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्ध विराम के बाद बनी सकारात्मक निवेश धारणा से सेंसेक्स 489.36 अंक की तेजी में 77,121.01 अंक पर खुला। चौतरफा लिवाली के बीच खबर लिखे जाते समय यह 655.61 अंक (0.86 प्रतिशत) ऊपर 77,287.26 अंक पर था। सेंसेक्स की कंपनियों में एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फिनसर्व से शेयरों में लिवाली ज्यादा रही।

3100 रुपये में खरीदे गये धान की अब 2000 रुपये में होगी नीलामी

राजनांदगांव। प्रदेश सरकार ने जिस धान को किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की ऊंची दर पर खरीदा था, अब उसे संग्रहण केंद्रों में रखे-रखे खराब होने से बचाने के लिए औने-पौने दामों पर बेचने की तैयारी की है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राजनांदगांव जिले के संग्रहण केंद्रों में लगभग नौ लाख क्विंटल अतिरिक्त धान जमा है। इस धान को निकालने के लिए सरकार ने ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आधार मूल्य बेहद कम रखा गया है। अब तक लगभग नौ राइस मिलर्स ने इस नीलामी में रुचि दिखाते हुए ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिये हैं। जानकारों का कहना है कि सरकार को केवल खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर से ही घाटा नहीं हो रहा है, बल्कि संग्रहण और परिवहन पर भी भारी खर्च हो चुका है। धान को खेतों से संग्रहण केंद्रों तक लाने में करोड़ों रुपये का परिवहन शुल्क चुकाया गया है। केंद्रों की देखरेख और सुरक्षा पर भी सरकार ने मोटी राशि खर्च की है।

3100 प्रति क्विंटल खरीदे गये धान को औसतन 2000 रुपये में बेचने पर सरकार को प्रति क्विंटल सीधे तौर पर 1100 रुपये का घाटा हो रहा है। मार्कफेड के अधिकारियों के अनुसार, नीलामी की पूरी प्रक्रिया रायपुर मुख्यालय के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जा रही है। मिलर्स द्वारा आवेदन जमा करने के बाद, नीलामी की प्रक्रिया पूरी होते ही डिलीवरी ऑर्डर जारी किये जाएंगे। इसके बाद ही मिलर्स सीधे संग्रहण केंद्रों से धान का उठाव शुरू कर सकेंगे। राजनांदगांव जिले में इस सीजन में रिकॉर्ड धान खरीदी हुई थी, लगभग 55.81 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, जिसमें से अब तक 57 लाख क्विंटल धान का उठाव हो चुका है। वर्तमान में संग्रहण केंद्रों में लगभग 70 हजार क्विंटल और मिलिंग के बाद अतिरिक्त पांच लाख क्विंटल धान शेष है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर मिलिंग न होने और उठाव में देरी के कारण धान की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, जिससे सरकार को और अधिक वित्तीय क्षति उठानी पड़ती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पद्मश्री जागेश्वर यादव के जीवन पर आधारित पुस्तक बिरहोर जननायक का किया विमोचन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पद्मश्री जागेश्वर यादव के जीवन पर आधारित पुस्तक बिरहोर जननायक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने पुस्तक के लेखक डॉ. लोकेश पटेल को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पद्मश्री जागेश्वर यादव का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन समाज के प्रति समर्पित रहा है और उनके कार्य विशेष रूप से जनसेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जशपुर जिले में 'बिरहोर के भाई' के रूप में विख्यात जागेश्वर यादव ने बिरहोर आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं, वे अत्यंत सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि उनका सरल व्यक्तित्व और समाज के प्रति अटूट प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा और संवेदनशीलता से ही जन्म लेता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बिरहोर जननायक पुस्तक उनके संघर्ष, समर्पण और सेवा की उस प्रेरक यात्रा को सामने लाती है, जो नई पीढ़ी को समाज के प्रति जागरूक और उत्तरदायी बनने की दिशा देती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कृति पाठकों को न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि समाज के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में भी सहायक होगी। इस अवसर पर पुस्तक के लेखक डॉ. लोकेश पटेल ने बताया कि इस पुस्तक की रचना आदिम जनजातियों, विशेषतः बिरहोर समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए जागेश्वर यादव द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि इस कृति में उनके जीवन संघर्ष, सामाजिक योगदान और मानवीय दृष्टिकोण को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

बंगाल में महिलाओं और बेरोजगारों को प्रतिमाह 3000 रूपए देने का वादा

कोलकाता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया जिसमें महिलाओं के लिए योजनाओं की भरमार है। शाह ने इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। साथ ही संकल्प पत्र में कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की पहल का वादा किया गया है। शाह ने कहा कि भाजपा राज्य में एक सशक्त स्थानीय नेतृत्व देने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में 'विश्वास का युग' लाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा और केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय में काम करेगा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य रखते हुये 'संकल्प पत्र' में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित एक व्यापक रोडमैप पेश किया है। भाजपा ने घोषणा पत्र में अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया है। इसके साथ ही राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति देने का भी ऐलान किया गया है। भाजपा ने महिलाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण और महिला पुलिस बटालियन व 'दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड' के गठन का वादा किया गया है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का वाद किया गया है। भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों का भी ध्यान रखा गया है। इसमें धान, आलू और आम की खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना से जोड़ने का वादा किया गया है, जिससे बंगाल को प्रमुख मछली निर्यातक राज्य बनाने की योजना है। भाजपा ने ताजपुर और कुलपी में डीप-सी पोर्ट विकसित करने, सिंगूर में औद्योगिक पार्क स्थापित करने और बंद पड़ी जूट मिलों को पुनर्जीवित करने की योजना पेश की है।

एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर से तोड़ा नाता

कोलकाता/हैदराबाद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने शुक्रवार को आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर के साथ अपना गठबंधन तोड़ने की घोषणा की है।

यह कदम हुमायूं कबीर से जुड़े विवादों और उन पर लगे आरोपों के बाद उठाया गया है। एआईएमआईएम का कहना है कि इन विवादों ने राज्य में मुसलमानों की अखंडता और प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। एआईएमआईएम ने स्पष्ट किया है कि वह अब पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में पार्टी ने कहा कि कबीर से जुड़े घटनाक्रमों ने बंगाल के मुस्लिम समुदाय की संवेदनशीलता को उजागर किया है और पार्टी ऐसे किसी भी बयान या कृत्य के साथ नहीं जुड़ सकती जो मुसलमानों की निष्ठा पर सवाल खड़ा करे। एआईएमआईएम ने कहा कि दशकों के धर्मनिरपेक्ष शासन के बावजूद बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और उत्पीड़ित समुदायों में बने हुए हैं। पार्टी ने जोर देकर कहा कि एआईएमआईएम का राजनीतिक उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को एक स्वतंत्र आवाज प्रदान करना है। साथ ही पार्टी ने यह भी घोषणा की कि भविष्य में पश्चिम बंगाल में उसका किसी भी राजनीतिक संगठन के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। यह अलगाव तब हुआ है जब राजनीतिक हलकों में एक कथित स्टिंग वीडियो सामने आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक ही वकील की ओर से पेश 25 जनहित याचिकाएं खारिज कीं

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक ही याचिकाकर्ता की ओर से व्यक्तिगत रूप से दायर 25 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पांचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील सचिन गुप्ता को जनहित याचिकाएं दायर करने के बजाय अपनी वकालत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने टिप्पणी की, पेशे पर ध्यान केंद्रित करें। जब सही समय होगा, हम मामलों पर भी विचार करेंगे। लेकिन पहले संवेदनशील बनें और मुद्दों को गहराई से समझें। अदालत के समक्ष पेश याचिकाओं में कई तरह की मांगें की गयी थीं। इनमें देश में प्रचलित सभी भाषाओं और बोलियों के शब्दों को मिलाकर भारत में एक सामान्य संपर्क भाषा विकसित करने की नीति, टेलीविजन पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के लिए नीति और साबुनों में रसायनों के उपयोग पर नीति बनाना शामिल था। इसके अलावा साबुनों में केवल ऐसे रसायनों की अनुमति देने की मांग की गयी थी, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हों न कि त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बैक्टीरिया को। याचिकाओं में अखिल भारतीय स्तर पर खाद्य/एफएसएसएआई

चुनाव आयोग ने बंगाल में 149 पुलिस अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाया

कोलकाता। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल पुलिस व्यवस्था में एक नये फेरबदल के तहत 81 पुलिस निरीक्षकों और 68 उप-निरीक्षकों को चुनाव संबंधी सभी कर्तव्यों से हटाने का आदेश दिया है। निर्वाचन निकाय ने स्पष्ट किया है कि ये अधिकारी अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी प्रक्रिया के किसी भी पहलू से नहीं जुड़ेंगे।

गुरुवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, हटाए गए निरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और उन्हें शुक्रवार शाम 5 बजे तक अपने संबंधित पदों पर कार्यभार संभालना होगा। आयोग ने संबंधित पुलिस अधीक्षकों को भी अनुपालन सुनिश्चित करने और लिखित में अनुपालन पत्र जमा करने का निर्देश दिया है कि ये अधिकारी किसी भी तरह से चुनाव संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

आयोग ने उप-निरीक्षकों से संबंधित एक अलग निर्देश में अपने पिछले 29 मार्च के आदेश का हवाला दिया, जब 150 निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को चुनाव ड्यूटी से हटाया गया था। उनमें से विभिन्न पुलिस थानों में कार्यरत 49 उप-निरीक्षकों को अब उनके वर्तमान जिलों से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने दोहराया कि उन्हें चुनाव संबंधी किसी भी जिम्मेदारी से पूरी तरह अलग रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त, एक अन्य अधिसूचना के तहत अन्य 19 उप-निरीक्षकों को विशेष रूप से चुनाव ड्यूटी से हटाने का आदेश दिया गया है।

हटाये गये निरीक्षकों की सूची राज्य के कई जिलों में फैली हुई है, जिनमें कूचबिहार, रायगंज, इस्लामपुर, अलीपुरद्वार, दक्षिण दिनाजपुर, सिलीगुड़ी, डायमंड हार्बर, बरुईपुर, बारासात, बशीरहाट, बनगाँव, बैरकपुर, बिधाननगर, कृष्णानगर, राणाघाट, आसनसोल-दुर्गापुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, मालदा और बांकुरा शामिल हैं, जो एक व्यापक प्रशासनिक हस्तक्षेप का संकेत देते हैं। पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होना है। चुनाव की घोषणा के बाद से, राज्य प्रशासन चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, जिसने प्रशासनिक और पुलिस तंत्र में व्यापक बदलाव किये हैं। मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त सहित प्रमुख पदों पर पहले ही फेरबदल किया जा चुका है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आयोग के आक्रामक प्रशासनिक उपायों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रैलियों में बार-बार निर्वाचन निकाय की आलोचना की है, उसके निर्णयों पर सवाल उठाए हैं और विशेष रूप से अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर अति-सक्रियता का आरोप लगाया है। इस बीच, कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार को चुनाव ड्यूटी से राहत नहीं दी गई है।

होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क लेना बंद करे ईरान : ट्रंप

नयी दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान से होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क लेना बंद करने को कहा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, ऐसी खबरें हैं कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क ले रहा है - उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर वे ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आवाजाही की अनुमति देकर बहुत ही खराब काम कर रहा है, कुछ लोग इसे अपमानजनक कहेंगे।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, यह हमारे समझौते के अनुरूप नहीं है। उन्होंने शुल्क का विवरण नहीं दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल पर जमकर हमला बोलते हुए ट्रंप ने इसे दुनिया के सबसे खराब और सबसे गलत संपादकीय बोर्डों में से एक बताया, क्योंकि जर्नल ने कहा था कि ट्रंप ने ईरान में समय से पहले जीत की घोषणा कर दी है। उन्होंने आगे कहा, दरअसल, यह एक जीत है, और इसमें समय से पहले की कोई बात नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्हीं की वजह से ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा, बहुत जल्द आप देखेंगे कि तेल का प्रवाह शुरू हो जाएगा, चाहे ईरान की मदद से हो या उसके बिना, और मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

ट्रंप ने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल हमेशा की तरह अपनी कही बात को वापस लेने के लिए मजबूर होगा।

सुकमा में मुख्यमंत्री बस्तर स्वास्थ्य योजना का होगा शुभारम्भ

स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को नई दिशा देगा वाइस चांसलर मीट-2026 : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

स्वस्थ नागरिक ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में आयोजित ऑल इंडिया हेल्थ साइंसेज वाइस चांसलर मीट-2026 को संबोधित करते हुए इसे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने भगवान श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर देशभर से आए कुलपतियों, शिक्षाविदों और विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पहली बार आयोजित इस एकदिवसीय सम्मेलन के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में नवाचारों का व्यापक आदान-प्रदान होगा, जो आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस मंच से निकले विचार न केवल नीति निर्माण को दिशा देंगे, बल्कि आमजन तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में भी सहायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेज, 14 नर्सिंग कॉलेज तथा एक होम्योपैथी कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला हैं और इसी दृष्टिकोण के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक की सहायता मिलना उनके लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीणों को कर्ज लेने या जमीन बेचने जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यह स्थिति तेजी से बदल रही है और स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियां, जो पहले सीमित वर्ग तक मानी जाती थीं, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रही हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरोग्य मंदिर जैसी पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में तीन आयुर्वेदिक एम्स स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य का लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, जो औषधीय पौधों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसी संदर्भ में उन्होंने हेमचंद मांझी को आयुर्वेद के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिलने पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पास कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचना के तेजी से विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि राजधानी क्षेत्र में मेडिसिटी हब विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 5000 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इससे प्रदेशवासियों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके कार्यकाल में रायपुर में एक दर्जन से अधिक निजी अस्पतालों का शुभारंभ किया गया है। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे महान शिक्षा केंद्रों का धनी रहा है और चिकित्सा व अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में विश्व गुरु के रूप में स्थापित रहा है।

राजस्व पखवाड़ा शिविर में 118 आवेदन प्राप्त, 96 का मौके पर निराकरण, ग्रामीणों को मिली त्वरित राहत

बेमेतरा/मूक पत्रिका

तहसील कार्यालय बेमेतरा द्वारा आयोजित राजस्व पखवाड़ा शिविर में विभिन्न ग्रामों से प्राप्त राजस्व संबंधी आवेदनों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण किया जा रहा है। प्रशासन की सक्रियता के चलते ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है तथा अनेक लंबित मामलों का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। आज कि स्थिति मे प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक शिविर में कुल 118 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है, जबकि शेष 22 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। अधिकारियों द्वारा इन लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शिविर में प्राप्त आवेदनों में सबसे अधिक संख्या आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र से संबंधित मामलों की रही। इस श्रेणी के कुल 51 आवेदन प्राप्त हुए थे और सभी 51 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया, जिससे आवेदकों को तत्काल राहत मिली। इसके अलावा फौती नामांतरण से संबंधित 11 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 5 का निराकरण किया गया है तथा 6 आवेदन लंबित हैं। वहीं बटवारा (विभाजन) संबंधी 7 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया एवं जांच जारी है।

अभिलेख सुधार से संबंधित कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 5 का निराकरण कर दिया गया है, जबकि 2 आवेदन लंबित हैं। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के 42 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 35 का समाधान कर दिया गया है तथा शेष 7 पर कार्यवाही जारी है।

ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंची समस्याएं-राजस्व पखवाड़ा शिविर में क्षेत्र के अनेक ग्रामों–खिराला, बंजडपुर, निम्हा, पथर्रा, जेवरा, गांगपुर, बहेरा, कुम्ही, अर्जुनी, झालम, झाल, बरखुवा, पेंड्रीतराई, मोहतरा, आरसिया, मुलमुला एवं चंदन सहित विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने अपनी-अपनी समस्याएं एवं आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर में पहुंचे नागरिकों ने बताया कि लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों का समाधान एक ही स्थान पर होने से उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है।

मौके पर ही किया गया निराकरण–शिविर के दौरान उपस्थित राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रत्येक आवेदन की बारीकी से जांच की गई तथा पात्र प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया गया। जिन मामलों में दस्तावेज या प्रक्रिया शेष है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन की पहल से बढ़ा विश्वास–तहसील प्रशासन की इस पहल से ग्रामीणों में संतोष एवं विश्वास का वातावरण बना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राजस्व पखवाड़ा का उद्देश्य लोगों को त्वरित, पारदर्शी एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि शेष लंबित आवेदनों का भी शीघ्र निराकरण कर सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

शासकीय प्राथमिक शाला खिलोरा में हुआ न्योता भोजन

बेमेतरा/खिलोरा/मूक पत्रिका

शासकीय प्राथमिक शाला खिलोरा में पदस्थ शिक्षिका श्रीमती ज्योति रेवेश्वर चंद्राकर को पुत्र रत्न प्राप्ति पर न्योता भोजन का आयोजन किया गया जिसमे शासकीय प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल व आँगनबाड़ी के बच्चो को खीर, पूड़ी, चावल, दाल, सब्जी, पापड़, सलाद, परोसा गया द्य गैंदराम वर्मा प्रधान पाठक ने शासन के महत्वांकांक्षी योजना न्योता भोजन के विषय में बच्चों व पलकों को बताया गया द्य न्योता भोजन कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सहायक संचालक एस पी कोशले, सुनील झा, श्रीमती कामनी महिलांगे विकास खंड शिक्षा अधिकारी, राजेंद्र साहू बी आर सी सी, रोशन साहू छात्रावास अधीक्षक, पी आर पात्रे संकुल प्राचार्य, नीलेश सोनी, डोमेन्द्र पाण्डेय, आकाश सोनी, हरनारायण रात्रे, संकुल समन्वयक, राधे साहू सरपंच, घनाराम साहू ग्राम पटेल, भुनेश्वर साहू पूर्व सरपंच, राहुल साहू विधायक प्रतिनिधि, कोमल साहू, रामचरण रजक, मनीष पाटिल प्रधान पाठक, मनोज वर्मा, लोमश पटेल, देवेंद्र साहू, देवेंद्र वर्मा, अजित बघेल, शिक्षक, श्रीमती निर्मला साहू प्रधान पाठक मिडिल स्कूल, मोहनी सोनी जोन के शिक्षक शिक्षिकाऐ व ग्रामवासियों की उपस्थिति रही।

राजस्व पखवाड़ा में हो रहा राजस्व कार्यों का त्वरित निराकरण, मल्दा ब में आयोजित किया गया क्लस्टर स्तरीय राजस्व शिविर

42 किसानों को प्रदान किये गए दस्तावेज

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे की अध्यक्षता में ग्राम मल्दा ब में गुरुवार को क्लस्टर स्तरीय राजस्व शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को अतिथियों, कलेक्टर, एसडीएम तहसीलदार के द्वारा राजस्व कार्य के त्वरित निराकरण की जानकारी दी गई। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक टीकाराम पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय, सदस्य हरिहर, एसडीएम वर्षा बंसल, डिप्टी कलेक्टर उमेश साहू, तहसीलदार एन के सिन्हा, प्रकाश पटेल सहित सारंगढ़ तहसील के राजस्व निरीक्षक, पटवारी सहित बड़ी संख्या में तहसील के ग्रामीण और किसान उपस्थित थे। इस दौरान अतिथियों ने बी 1 नकल, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, वृक्ष कटाई की अनुमति, द्वितीय प्रति किसान किताब, आय-जाति- निवास प्रमाण पत्र, अभिलेख त्रुटि सुधार, रिकॉर्ड दुरूस्ती तथा वन पट्टा का फौती नामांतरण, प्राकृतिक आपदा इत्यादि प्रकरणों के दस्तावेज 42 किसानों को वितरित किये। किसानों ने अपने कार्य के शीघ्र निराकरण के कार्यवाही को मंच के माध्यम से सबके सामने बखान किया और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित पूरे जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्राथमिक शाला खैरगुड़ा में विदाई समारोह व न्यौता भोज का भव्य आयोजनः शिक्षा, संस्कार और समुदाय का अनुपम संगम

बस्तर/मूक पत्रिका

बस्तर विकासखंड के संकुल केंद्र कुंडगुड़ा के अंतर्गत संचालित प्राथमिक शाला खैरगुड़ा का परिसर शुक्रवार को एक ऐतिहासिक और भावपूर्ण दिन का साक्षी बना। विद्यालय प्रांगण में कक्षा पांचवीं के बच्चों के लिए विदाई समारोह के साथ न्यौता भोज का भव्य और गरिमामय आयोजन किया गया। यह आयोजन केवल एक औपचारिक रस्म अदायगी तक सीमित नहीं रहा बल्कि शिक्षा, संस्कार और सामुदायिक सहभागिता का जीवंत उत्सव बन गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर आम ग्रामीणों तक की उत्साहपूर्ण और सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। पूरे परिसर में उल्लास, अपनापन और भावुकता का अद्भुत संगम दिखाई दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य शकुंतला कश्यप उपस्थित रहीं और कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच कुंडगुड़ा ईश्वर मंडावी ने की। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष बस्तर सुखदेव मंडावी, जनपद सदस्य समली कश्यप, उपसरपंच कुंडगुड़ा सामबती ठाकुर तथा वरिष्ठ नागरिक तयसिंह ठाकुर विराजमान रहे। इनके साथ ही ग्राम पटेल उर्धेश्वर ठाकुर, संजय सिंह ठाकुर, गिरीराम, मनोज कुमार,केशव ठाकुर, लोकनाथ ठाकुर, झुमुकलाल, टिकमचंद ,जगरू कश्यप,भूषण बघेल,कुसुम शार्दूल, जंयती,बालमती, कुसुमलता, हेमबती, उर्मिला, भूमिता, बालमती ठाकुर, सतबती, माधुरी, मंदना, आयती समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, पालकगण, स्व-सहायता समूह की महिलाएं और ग्रामीणजन सपरिवार उपस्थित थे। अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति ने विद्यालय परिवार और बच्चों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाध्यापक छन्नूराम मंडावी के कुशल नेतृत्व में हुए आत्मीय स्वागत से हुई। शिक्षिका इंदुमती बाई, संकुल समन्वयक कृष्णा सिंह ठाकुर, शिक्षक लोकेश्वर यदू, योगेंद्र कुमार निषाद एवं मनोज कुमार ठाकुर सहित समस्त शिक्षकगण ने पुष्पगुच्छ भेंट कर और तिलक लगाकर सभी अतिथियों का पारंपरिक रीति से अभिनंदन किया। स्वागत में दिखी सादगी और अपनापन ने माहौल को शुरुआत से ही पूरी तरह भावनात्मक बना दिया। इसके बाद समारोह का मुख्य आकर्षण बना बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम। नन्हे विद्यार्थियों ने बस्तर की समृद्ध लोकसंस्कृति को दर्शाते हुए पारंपरिक लोकगीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। समूहगान, कविता पाठ और नाटिका के माध्यम से उन्होंने शिक्षा का महत्व और सामाजिक संदेश भी दिया। बच्चों की सहजता, आत्मविश्वास और मंच पर दिखी प्रतिभा को देखकर उपस्थित हर व्यक्ति भावविभोर हो गया और करतल ध्वनि से उनका उत्साहवर्धन करता रहा। विदाई की बेला आते ही पूरा माहौल भावुक हो उठा। अगली कक्षा में जाने वाले बच्चों को शिक्षकों ने तिलक लगाकर, मुंह मीठा कराकर और स्मृति चिह्न भेंट कर स्नेहपूर्वक विदा किया। इस दौरान कई बच्चों और शिक्षकों की आंखें नम हो गईं। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि श्रीमती शकुंतला कश्यप ने कहा कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं और इनकी नींव जितनी मजबूत होगी, हमारा समाज और राष्ट्र उतना ही सशक्त बनेगा। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे शिक्षकों के प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की। सरपंच श्री ईश्वर मंडावी ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और पालकों से अपील की कि वे बच्चों की पढ़ाई पर निरंतर ध्यान दें।

1बंद योजनाओं के जमा अवशेष राशि के सम्बन्ध में कलेक्टर ने ली बैठक, सभी चिन्हित डीडीओ को कलेक्टर ने प्रक्रिया पालन करने के निर्देश दिए

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

कलेक्टर एवं जिला प्रमुख डॉ संजय कन्नौजे की अध्यक्षता में वित्तीय मामलों से जुड़े बंद योजनाओं के अवशेष राशि को जमा करने के सम्बन्ध में जिले के चिन्हित आहरण एवं संवितरण (डीडीओ) अधिकारियो के साथ कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में बैठक लिया गया। कलेक्टर ने ऐसे बैंक खाता से प्रक्रिया पालन करने के निर्देश दिए। जिला कोषालय अधिकारी उत्तम तुरकाने ने कहा कि, ऐसे बैंक खाता जिसमें राशि 10 साल से अधिक अवधि तक जमा है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का पालन कर वह राशि प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर उप कोषालय अधिकारी हरिराम पटेल उपस्थित थे।

डीफ बैंक अकाउंट क्या है ?

डीफ बैंक अकाउंट वह होता है जिसमें 10 साल से अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है। ऐसे अकाउंट्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीफ) में ट्रांसफर कर दिया जाता है

डेफ बैंक अकाउंट को एक्टिव करने के लिए:

- बैंक में जाकर केवाईसी अपडेशन कराएं
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें, जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, आदि- बैंक में एक डेबिट लेन-देन करे।

आरबीआई के नियम :- 2 साल से अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं होने पर अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है - 10 साल से अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं होने पर अकाउंट डीफ हो जाता है- अगर किसी व्यक्ति या उसके बुजुर्ग या कोई भी उम्र के व्यक्ति जिनका 10 साल पुराना पैसा जमा है वो बैंक अकाउंट डीफ हो गया है, तो आप बैंक में जाकर इसे एक्टिव करा सकते हैं और जमा राशि वापस पा सकते हैं।यदि कोई बैंक खाता 10 वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय (कोई लेन-देन नहीं हुआ) है, तो उसे लावारिस खाता मानकर आरबीआई के जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह धनराशि सुरक्षित रहती है और आप अपने बैंक को केवाईसी दस्तावेज़ सहित एक अनुरोध भेजकर मूल खाताधारक, उत्तराधिकारी या कानूनी वारिस दावा शुरू कर इसे प्राप्त कर सकते हैं।

एनएसयूआई से युवा कांग्रेस तकः परमेश्वर बने जिला सचिव, कार्यकर्ताओं में उत्साह

बेमेतरा/मूक पत्रिका

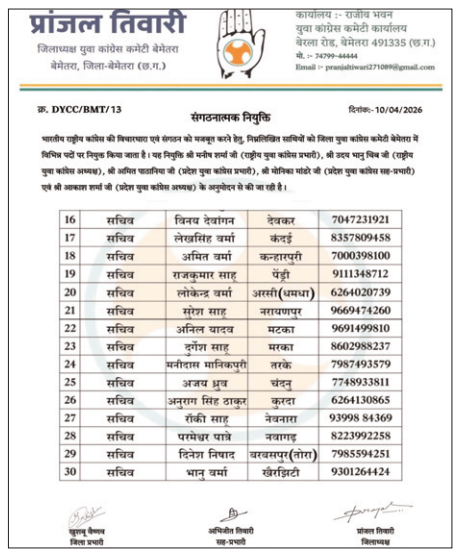

जिले में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में युवा नेता परमेश्वर को युवा कांग्रेस का जिला सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद जिले के युवा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। परमेश्वर इससे पहले नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने शहर अध्यक्ष, नवागढ़ जिला महासचिव तथा जिला उपाध्यक्ष जैसे पदों पर रहते हुए संगठनात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उनकी सक्रियता को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए यह नई जिम्मेदारी सौंपी है। समर्थकों का कहना है कि उनके नेतृत्व में संगठन को नई मजबूती मिलेगी और युवाओं की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा। जिम्मेदारी मिलने पर परमेश्वर ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने तथा अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

प्रांजल तिवारी
जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस कमेटी बेमेतरा
बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

कार्यालय :- राजीव भवन
युवा कांग्रेस कमेटी कार्यालय
बेरला रोड, बेमेतरा 491335 (छ.ग.)
मो. :- 74799-44444
Email :- pranjaltiwari271089@gmail.com

क्र. DYCC/BMT/13 — संगठनात्मक नियुक्ति — दिनांक:- 10/04/2026

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा एवं संगठन को मजबूत करने हेतु, निम्नलिखित साथियों को जिला युवा कांग्रेस कमेटी बेमेतरा में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति श्री मनीष शर्मा जी (राष्ट्रीय युवा कांग्रेस प्रभारी), श्री उदय भानु चिब जी (राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष), श्री अमित पाठानिया जी (प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी), श्री मोनिका मांडरे जी (प्रदेश युवा कांग्रेस सह-प्रभारी) एवं श्री आकाश शर्मा जी (प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष) के अनुमोदन से की जा रही है।

16	सचिव	विनय देवांगन	देवकर	7047231921
17	सचिव	लेखसिंह वर्मा	कंदई	8357809458
18	सचिव	अमित वर्मा	कन्हारपुरी	7000398100
19	सचिव	राजकुमार साहू	पेंड्री	9111348712
20	सचिव	लोकेन्द्र वर्मा	अरसी(धमधा)	6264020739
21	सचिव	सुरेश साहू	नरायणपुर	9669474260
22	सचिव	अनिल यादव	मटका	9691499810
23	सचिव	दुर्गेश साहू	मरका	8602988237
24	सचिव	मनीदास मानिकपुरी	तरके	7987493579
25	सचिव	अजय ध्रुव	चंदनु	7748933811
26	सचिव	अनुराग सिंह ठाकुर	कुरदा	6264130865
27	सचिव	रॉकी साहू	नेवनारा	93998 84369
28	सचिव	परमेश्वर पात्रे	नवागढ़	8223992258
29	सचिव	दिनेश निषाद	बरबसपुर(तोरा)	7985594251
30	सचिव	भानु वर्मा	खैरझिटी	9301264424

खुशबू वैष्णव, जिला प्रभारी — अभिजीत तिवारी, सह-प्रभारी — प्रांजल तिवारी, जिलाध्यक्ष

खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई

अवैध मिट्टी-मुरूम उत्खनन एवं परिवहन पर सख्त कार्यवाही, 7 वाहन जब्त

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। प्राप्त शिकायत के आधार पर ग्राम टिपनी, तहसील थानखमरिया क्षेत्र में मिट्टी एवं मुरूम के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की जांच की गई। यह संपूर्ण कार्रवाई विभागीय टीम द्वारा पंचगणों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर की गई, जिससे जांच प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं नियमानुसार संपन्न हो सके।

शिकायत के आधार पर किया गया स्थल निरीक्षण–सूत्रों से प्राप्त शिकायत में ग्राम टिपनी क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी एवं मुरूम का उत्खनन कर बिना वैध अनुमति के परिवहन किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खनिज विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और विस्तृत जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा उत्खनन गतिविधियों के साक्ष्य एकत्रित किए गए। जांच दल द्वारा यह पाया गया कि संबंधित क्षेत्र में बिना वैध खनिज अनुज्ञा पत्र एवं परिवहन पास के भारी मशीनरी एवं वाहनों के माध्यम से खनिज सामग्री का अवैध उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा था।

मौके पर भारी मशीनरी एवं वाहन जब्त–जांच के दौरान अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलग्न पाए गए वाहनों पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके से कुल 1 नग जेसीबी मशीन (छ्वष्टक्च) एवं 2 नग हाईवा वाहन को जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त अवैध परिवहन के प्रकरण में अलग-अलग स्थानों से निम्न वाहन भी जब्त किए गए जिसमे 1 हाईवा वाहन जिसमें रेत खनिज भरा हुआ था 7 1 हाईवा वाहन जिसमें चूना पत्थर (गिट्टी) खनिज भरा हुआ था 7 इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में भी 1 हाईवा वाहन जिसमें रेत खनिज तथा 1 हाईवा वाहन जिसमें मुरूम खनिज लदा हुआ पाया गया, जिसे भी जब्त किया गया।

थाना स्तर पर सुरक्षार्थ खड़ी की गई वाहन–जप्त किए गए सभी वाहनों को नियमानुसार सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित थाना क्षेत्रों में खड़ा कराया गया है। कुछ वाहन थाना थानखमरिया में तथा कुछ वाहन थाना बेमेतरा में सुरक्षार्थ रखे गए हैं 7 इस प्रकार कुल 7 वाहनों को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है, ताकि आगे की विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

पंचगणों की उपस्थिति में पारदर्शी जांच–पूरी कार्रवाई पंचगणों की उपस्थिति में की गई, जिससे जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। मौके पर ग्रामीणों की उपस्थिति में उत्खनन स्थल का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक पंचनामा तैयार किया गया। विभागीय अधिकारियों द्वारा सभी साक्ष्य संकलित किए गए और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। खनिज विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में किसी भी प्रकार के अवैध खनिज उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है तथा सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई की जा रही है।विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध खनन से शासन को राजस्व की हानि होती है तथा पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नियमानुसार आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन–जप्त किए गए सभी 7 वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संबंधित वाहन मालिकों एवं संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध खनिज अधिनियम एवं अन्य प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि कहीं भी अवैध खनन या परिवहन की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके।

4 नई डोलोमाइट खदानों के लिए जनसुनवाई हुई संपन्न, दूसरा दिन रहा शांतिपूर्ण, खदान विस्तार को मिला जनसमर्थन..

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कटंगपाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोंदा स्थित सहकारी समिति प्रांगण में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण जनसुनवाई का आयोजन किया गया। यह जनसुनवाई आर्यन मिनरल्स एंड मेटल्स जोतपुर-दुलमपुर-मौहापाली सहित शुभ मिनरल्स कटंगपाली, मंगल मेटल छैलफेरा और बालाजी माइंस एंड मिनरल्स जोतपुर की डोलोमाइट पत्थर खदानों के क्षमता विस्तार के लिए बुलाई गई थी। बता दें कि तहसील मुख्यालय सरिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोंदा में सोमवार और मंगलवार को प्रस्तावित 4 नई डोलोमाइट पत्थर खदानों के लिए दो दिवसीय जनसुनवाई आयोजित की गई थी।

एक ओर जहां जनसुनवाई के पहले दिन ग्रामीणों ने इसे रोजगार का अवसर बताकर समर्थन किया और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसानों ने पर्यावरण और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। वही दूसरी ओर जनसुनवाई के दूसरे दिन किसी प्रकार का कोई विरोध दर्ज नहीं किया गया। पीठासीन अधिकारी व सारंगढ़ एसडीएम डॉ वर्षा बंसल ने जनसुनवाई की अध्यक्षता की।

जनसुनवाई के दूसरे दिन सुबह 10 बजे शुरू हुई इस प्रक्रिया में पहले दिन की तुलना में भीड़ कम थी और पुलिस बल की भी आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। एसडीएम डॉ वर्षा बंसल ने उपस्थित जनसमुदाय, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष खसरा नंबर 160/1क से लेकर 160/25 तक के कुल 4.961 हेक्टेयर रकबे में क्षमता विस्तार के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए पक्ष और विपक्ष से सुझाव आमंत्रित किए।

स्थानीय विकास और रोजगार पर जोर

समर्थन की शुरुआत ग्राम पंचायत बोंदा के सरपंच गोवर्धन निषाद ने की। उन्होंने मंच से कहा कि खदानों के विस्तार से क्षेत्र के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे न केवल गांवों के विकास को गति मिलेगी, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार की उम्मीद है। सरपंच के साथ ही बोंदा की महिला पंच गीता रात्रे, बोकरामुडा के विक्रम सिदार, कटंगपाली के रमाकांत साहू, बांजीपाली के उमेश पटेल और बिलाईगढ़-अ के रवि पटेल सहित कुल 35 लोगों ने लिखित में अपना समर्थन पत्र सौंपा। इसके अतिरिक्त, लगभग 150 अन्य ग्रामीणों ने भी मौखिक रूप से विस्तार योजना का समर्थन किया।

विरोधियों के बदले सुर, दिए सकारात्मक सुझाव

जनसुनवाई का सबसे दिलचस्प पहलू वह रहा जब पूर्व में विरोधाभास रखने वाले चेहरों ने भी विकास के पक्ष में अपनी बात रखी। बोंदा के नितिन पाणिग्राही, सुरेन्द्र सिंह सिदार और सुखापाली के उप सरपंच लोकनाथ नायक, जो पहले खदानों को लेकर संशय में थे, मंगलवार को उनके सुर बदले हुए नज़र आए। उन्होंने माइक पर आकर खदान मालिकों को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें प्रदूषण मुक्त कार्य प्रणाली अपनाने, अधिक से अधिक पेड़ लगाने और सड़कों पर धूल न उड़े इसके लिए नियमित पानी छिड़काव कराने की बात कही। साथ ही, उन्होंने डोलोमाइट पत्थर के सुरक्षित परिवहन (ओवरलोडिंग से बचाव) पर भी जोर दिया।

दूसरे दिन महज एक घंटे में पूरी हुई औपचारिकता

जनसुवाई के दूसरेबदीन किसी भी प्रकार का विरोध या आपत्ति सामने न आने के कारण एसडीएम वर्षा बंसल ने परियोजना प्रस्तावक को विस्तार योजना की जानकारी पढ़ने के निर्देश दिए और महज एक घंटे के भीतर जनसुनवाई के समापन की घोषणा कर दी। इस अवसर पर पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू, तहसीलदार कोमल प्रसाद साहू और पुलिस विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे।

रायगढ़ के पंचायत सचिव ने डकारे लाखों रूपए

रायगढ/मूक पत्रिका

ग्राम पंचायत बरभौना के सचिव पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए उसके विरूद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के मरम्मत के लिए आई राशि में से बाहरी रंग रोगन कराकर शेष राशि का गबन करने का आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत बरभौना के सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों द्वारा दिये गये ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायत में पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के मरम्मत के लिए आई राशि में से बाहरी रंग रोगन कराकर शेष राशि का फर्जी बिल प्रस्तुत कर सचिव रामप्रसाद डनसेना द्वारा गबन कर लिया गया है। सचिव द्वारा ग्राम सभा का आयोजन भी नहीं किया जाता है और पंचों की सहमति के बिना मनमानी ढंग से निर्णय ले लिया जाता है। गांव के तालाब में जल भराव नहीं होने की स्थिति में जहां निस्तारी की समस्या हो रही है तोवहीं पशुओं को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसकी व्यवस्था करने में भी सचिव कोई रूचि नहीं दिखा रहा है। वहीं नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण जन्मप्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जैसे कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से उचिवत कार्रवाई कर राहत दिलाने की गुहार लगाई है।

अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई, लगभग 200 ट्रैक्टर अवैध रेत नदी में वापस डलवाया गया, 2 हाईवा वाहन जब्त

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर नियंत्रण हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा ग्राम नवापारा में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई की गई। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान स्थल पर अवैध रेत भंडारण पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही नदी किनारे डंप लगभग 200 ट्रैक्टर रेत को वापस नदी में डलवाया गया।कार्रवाई के दौरान अवैध परिवहन में संलिप्त 02 हाईवा वाहनों को जब्त कर पुलिस लाइन में सुरक्षार्थ रखा गया है।दर्ज प्रकरण पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

प्रश्न पत्र छपाई को लेकर फिर घिरा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय

स्थानीय प्रेस को दरकिनार कर बिहार में छपाई कराने की चर्चा, निविदा प्रक्रिया पर उठे सवाल

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जांजगीर-चांपा अपने अजीबो-गरीब कारनामों को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी फर्जी शिक्षाकर्मियों से मासिक वसूली के आरोप, कभी अपात्रों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की चर्चाएं, तो कभी शिक्षकों की मनचाही पदस्थापना और अपात्र लोगों को पदोन्नति का लाभ देने जैसे मामलों को लेकर विभाग पहले ही विवादों में रहा है। अब एक नया मामला सामने आया है, जिसमें विद्यालयों के लिए प्रश्न पत्रों की छपाई को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा मामला जिले के स्कूलों में आयोजित परीक्षाओं के लिए कक्षा पहली से लेकर कक्षा 11वीं तक

के प्रश्न पत्रों की छपाई से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के अनुसार इन कक्षाओं के प्रश्न पत्र जिले या प्रदेश के किसी स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने के बजाय बिहार राज्य के किसी प्रिंटिंग प्रेस से छपवाए जाने की चर्चा है। इस बात को लेकर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि सामान्यतः इस प्रकार के कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर या राज्य के भीतर ही प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से प्रश्न पत्र छपवाए जाते हैं, जिससे समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और गोपनीयता भी बनी रहे। लेकिन इस बार जिले से बाहर दूसरे राज्य में छपाई कराए जाने की बात सामने आने से कई तरह की शंकाएं पैदा हो गई हैं। इधर प्रश्न पत्र छपाई के लिए अपनाई गई निविदा प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रश्न पत्र छपाई के लिए निविदा आमंत्रण की सूचना कब जारी की गई थी और इस प्रक्रिया में कितने लोगों या संस्थाओं ने निविदा प्रस्तुत की थी। सूत्रों का दावा है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने नहीं आई है। इसके अलावा यह भी चर्चा है कि प्रश्न पत्र छपाई का कार्य किस दर पर और किस आधार पर संबंधित प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया, इस संबंध में भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। शिक्षा से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रश्न पत्र छपाई जैसा कार्य बेहद संवेदनशील होता है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर हजारों विद्यार्थियों की परीक्षाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे में निविदा प्रक्रिया और छपाई व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर विभाग की भूमिका पर निगाहें टिक गई हैं। यदि मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो प्रश्न पत्र छपाई की प्रक्रिया से जुड़े कई तथ्य सामने आ सकते हैं।

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले की एकीकृत बाल विकास परियोजना बेमेतरा अंतर्गत वर्तमान में नवीन स्वीकृत पद एवं रिक्त पद हेतु आ.बा. सहायिका के पद पर शासन द्वारा निर्धारित निर्देश एवं मानदंडों के अनुसार नियमानुसार नियुक्ति किया जाना हैं। इसके अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना विकासखण्ड बेमेतरा नगर पालिका वार्ड नं. 08 कोबिया (नया वार्ड 09) आम्बेडकर वार्ड मे आं.बा. सहायिका के 01 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया हैं।

आवेदन संबंधित नगरीय की आवेदिकाओ द्वारा आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि में 08 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय बेमेतरा में कार्यालयीन समय 10:00 से 5:30 बजे तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक द्वारा जमा किये जायेगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगे। आंगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं निर्धारित उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होना चाहिए। एक वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदिका को ग्रामीण क्षेत्रों में उसी नगरी वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तथा नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन पत्र सम्बन्धित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

विधायक ब्यास के प्रयास से नगर सहित क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए मिली करोड़ो की स्वीकृति

जांजगीर-चांपा /मूक पत्रिका

विधायक ब्यास कश्यप के प्रयास से जांजगीर-चांपा विधानसभा के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यो को स्वीकृति प्रदान किया गया है। इन कार्यो में प्रमुख रूप से पहुंच मार्गों का उन्नयन कार्य, मजबूतीकरण तथा चैड़ीकरण एवं विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं। विधायक कार्यालय जांजगीर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधान सभा जांजगीर-चांपा क्षेत्र के ग्राम बुड़ेना से ग्राम भैंसमुड़ी तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 3.50 करोड़ रूपए, जिला पंचायत मोड़ से ग्राम पेण्ड्री (जांजगीर) पहुंच मार्ग के चैड़ीकरण के लिए 3.98 करोड़ रूपए, जांजगीर नगर के बी.टी.आई. चैक से खोखसा ओव्हरब्रिज तक सड़क में डिवाईडर एवं विद्युतीकरण कार्य

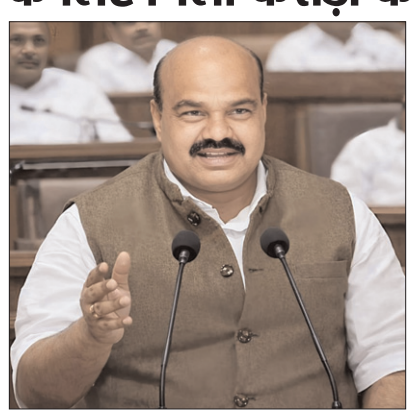

के लिए 1.11 करोड़ रूपए, मुख्य मार्ग से बनारी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य 700 मीटर के लिए 15.25 लाख, ग्राम बोड़सरा से सिवनी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए 53.94 लाख रूपए, जांजगीर बाईपास पास लिंक रोड निर्माण के लिए 78.00 लाख रूपए, जांजगीर-केरा मार्ग चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य 600 मीटर के लिए 31.75 लाख रूपए, की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सभी कार्यो की स्वीकृति जिला खनिज संस्थान न्यास मद से दी गई है। इस क्षेत्र के ग्रामीण वर्षो से जर्जर एवं संकरे सड़क के कारण मुसीबतें झेल रहे थे। विधायक ब्यास कश्यप ने जनता की समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए इनक कार्यो को स्वीकृति दिलाई है। इन सड़को के निर्माण, चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण से न केवल कनेक्टिविटी सुधरेगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा। विधायक ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि जनता को बेहतर बुनियादी ढांचा मिल सके। वर्षो पुरानी मांगें पूरी होने पर स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है और उन्होंने विधायक ब्यास कश्यप का आभार जताया है।

जागा प्रशासनः अंबेडकर भवन पहुंचे अधिकारी, प्रतिमा स्थापना का दिया आश्वासन

चांपा/मूक पत्रिका

नगर पालिका परिषद चांपा के वार्ड क्रमांक 20 स्थित अंबेडकर भवन में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना की मांग को लेकर उठे विवाद के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। मीडिया में मामला प्रमुखता से सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद दुर्गा प्रसाद कुर्रे द्वारा अंबेडकर भवन में प्रतिमा स्थापना की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था साथ ही 14 अप्रैल 2026 को अंबेडकर जयंती से पूर्व मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ा। नगर पालिका परिषद चांपा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चांपा थाना प्रभारी,

तहसीलदार, नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप नामदेव एवं पार्षदगण अंबेडकर भवन पहुंचे। अधिकारियों ने रामबांधा तालाब के समीप स्थित भवन का निरीक्षण किया और वहां की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान पार्षद दुर्गा प्रसाद कुर्रे ने अधिकारियों को बताया कि अंबेडकर भवन में वर्षों से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शासकीय कार्यक्रम आयोजित होते आ रहे हैं, लेकिन अब तक बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है, जिससे आम नागरिकों और समाज के लोगों में नाराजगी व्याप्त है। अधिकारियों ने पार्षद एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि प्रतिमा स्थापना के संबंध में जल्द ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उचित निर्णय लिया जाएगा। प्रशासनिक आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन की स्थिति टलती नजर आ रही है, हालांकि अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अंबेडकर जयंती से पहले मांग पूरी होती है या नहीं।

विकास कार्यों में राशि का बंदरबाट, बिना काम के ठेकेदार को किया भुगतान

पुसौर नगर पंचायत बना अनियमितताओं का गढ़, अधिकारी बने अनजान

रायगढ़/मूक पत्रिका

जिले के पुसौर नगर पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। कागजों में लाखों रुपये के विकास कार्य पूरे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर उनकी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना काम कराए ही फर्जी दस्तावेजों के सहारे भुगतान कर दिया गया है।इस पूरे मामले में नगर पंचायत के अधिकारी जांच कर प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को सौंपने की बात कही जा रही है।बहरहाल देखना लाजमी होगा कि क्या अब इस गड़बड़ी में दोषियों पर कोई कार्यवाही होगी।या फिर लापरवाही बरती जाएगी। गौरतलब हो कि पूरा मामला पुसौर नगर पंचायत का है। जिसके बोरोडीपा से बाजार चौक मार्ग में रिकॉर्ड अनुसार एलईडी लाइट और इलेक्ट्रिक पोल लगाने का कार्य पूर्ण बताया गया है। दस्तावेजों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस कार्य के लिए करीब 16 लाख रुपये का

भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया। लेकिन जब मौके पर स्थिति देखी गई तो वहां दूर-दूर तक नए पोल या एलईडी लाइट नजर नहीं आए। सड़क किनारे सिर्फ पुराने बिजली के खंभे ही दिखाई देते हैं।ऐसे में यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब मौके पर काम हुआ ही नहीं, तो आखिर 16 लाख रुपये का भुगतान किस आधार पर किया गया। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर पंचायत में कागजी कार्यवाही पूरी कर फर्जी तरीके से भुगतान निकालने का खेल लंबे समय से चल रहा है।यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले वार्ड क्रमांक 14 और वार्ड क्रमांक 2 में नाली निर्माण के नाम पर भी लाखों रुपये की अनियमितता के आरोप सामने आ चुके हैं। आरोप है कि बिना निर्माण कार्य किए ही फर्जी बिल, फर्जी माप पुस्तिका और दस्तावेज तैयार कर भुगतान निकाल लिया गया।बताया जा रहा कि पूर्व में हुए कई कथित निर्माण कार्यों का भुगतान भी एक ही ठेकेदार को किया गया है। इससे पूरे मामले में मिलीभगत की आशंका और गहरा रही है। नगर पंचायत उनसे नियमित रूप से टैक्स वसूलती है, लेकिन बदले में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है।

आधा दर्जन मामले सामने-सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह के लगभग आधा दर्जन मामले सामने आने के बावजूद अब तक जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतें जिला प्रशासन तक भी पहुंच चुकी हैं और कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी को भी इस पूरे मामले से अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है।अब लोगों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।

रिकॉर्ड में लाइट और पोल, मौके पर सिर्फ पुराने खंभे-पुसौर के बोरोडीपा से बाजार चौक मार्ग में एलईडी लाइट और इलेक्ट्रिक पोल लगाने का कार्य कागजों में पूरा दिखाया गया है। इसके लिए करीब 16 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। लेकिन मौके पर स्थिति यह है कि वहां नए पोल या एलईडी लाइट दिखाई ही नहीं देते, बल्कि केवल पुराने बिजली के खंभे मौजूद हैं।

पहले भी सामने आ चुके हैं कई मामले-नगर पंचायत में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले वार्ड 14 और वार्ड 2 में नाली निर्माण के नाम पर भी लाखों रुपये निकालने के आरोप लग चुके हैं। आरोप है कि फर्जी बिल और दस्तावेजों के आधार पर भुगतान किया गया।

क्या कहते है सी. एम. ओ.नगर पंचायत पुसौर -ललित कुमार साहू =उस दौरान तीन टेंडर निकाले गए थे।तीनो की जांच की जा रही है।पुसौर के बोरोडीपा चौक में पोल और लाइटें नहीं लगाई गई।जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे।उनके निर्देशानुसार दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी

लू-तापघात से बचाव हेतु शासन ने जारी किए दिशा-निर्देश, जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर द्वारा ग्रीष्म ऋतु के दौरान संभावित लू-तापघात (हीट वेव) से बचाव एवं आवश्यक तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार लू-तापघात से बचाव संबंधी जानकारी को व्यापक रूप से जन-जन तक पहुँचाने के लिए जिला, तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सघन प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों एवं कोटवारों की सहायता से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि आमजन समय रहते आवश्यक सावधानियाँ अपना सकें। इसी क्रम में जिले में लू-तापघात से बचाव एवं आपदा की स्थिति में समुचित समन्वय हेतु सुश्री पिंकी मनहर, डिप्टी कलेक्टर, बेमेतरा को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

किसी भी आपात स्थिति अथवा सूचना के लिए उनसे मोबाइल/व्हाट्सऐप नंबर 87704-22395 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि भीषण गर्मी के समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें तथा लू-तापघात से बचाव के सभी आवश्यक उपाय अपनाकर स्वयं एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखें।

संपादकीय

युद्ध की आग में झुलसती रसोई, जमाखोरी और महंगाई की दोहरी मार

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच होर्मुज जलमार्ग के बंद होने से उपजा संकट अब गहराने लगा है। युद्ध 39वें दिन में पहुँच गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने से भारत समेत कई देशों में ईंधन की उपलब्धता काफी कम हो गई है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। देश में सरकार की ओर से भले ही यह दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन हाल में व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर और विमान ईंधन की कीमतों में की गई बढ़ोतरी से स्पष्ट है कि संकट धीरे-धीरे अपने पांव पसार रहा है।सरकार देश भर में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में देरी को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे लोगों में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। इस बीच, पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी ने समस्या को और बढ़ा दिया है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को घरों में ईंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाने और ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने को भी कहा गया है।गौरतलब है कि ईरान तथा इजराइल-अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के करीब एक माह बाद कई देशों में तेल और गैस का व्यापक संकट खड़ा हो गया है। ईरान ने जब से होर्मुज जलमार्ग को बंद किया है, उसके बाद भारत सहित कई देशों में बड़े पैमाने पर तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। ईंधन की कमी से उपजा वैश्विक संकट अब जिस स्तर पर बढ़ता जा रहा है, उसका भारत पर भी गहरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वह कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर अधिक निर्भर है।ऐसे में अगर युद्ध लंबा खिंचा तो आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक उपायों पर अब व्यापक स्तर पर और गंभीरता से विचार करना होगा।देश में सरकार के समक्ष चुनौती सिर्फ तेल और गैस की कमी की ही नहीं है, बल्कि इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की भी है। मौजूदा संकट का दायरा इसलिए भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपदा में अवसर तलाशने वालों में मुनाफा कमाने की होड़ लग गई है। जमाखोरी कर रसोई गैस सिलेंडर ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं, जिससे जरूरतमंद आम लोगों को कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है।ऐसे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार की ओर से ऊर्जा के वैकल्पिक उपायों के तौर पर लोगों को घरों में इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक कुकटाप जैसे साधनों का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जा रही है, ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम की जा सके।

आधुनिकता का अर्थ क्या यह हो गया है कि इस देश की आधी कार्य योग्य आबादी अपनी समस्याओं के बारे में न सोचे और नशे में ही डूबी रहे? आज के युवा जिस तरह का नशा कर रहे हैं, उसमें मदिरा और कच्ची शराब पुरानी चीजें हो गई हैं। अब हुक्का बार और अन्य मादक पदार्थों के सेवन के मामले देखे जा रहे हैं। सिंथेटिक नशे का दौर आ गया लगता है। गौरतलब है कि नशे का कारोबार इतना बड़ा हो गया है कि किसी भी राज्य में नशे का धंधा करने वाले या इस व्यापार के सूत्रधार देश के सुदूर कोने या विदेश में भी मिल सकते हैं।

नशामुक्ति में जनसहयोग की जरूरत, युवाओं, समाज और व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती

(सुरेश सेठ)

पंजाब में नशाखोरी के खिलाफ पिछले एक वर्ष से अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने छापे मार कर सैकड़ों तस्कर पकड़े हैं। इनमें से बहुत सारे आरोपियों को सजा भी दिलवाई है। हजारों किलो नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। मगर समस्या दूर नहीं हुई है।

आधुनिकता का अर्थ क्या यह हो गया है कि इस देश की आधी कार्य योग्य आबादी अपनी समस्याओं के बारे में न सोचे और नशे में ही डूबी रहे? आज के युवा जिस तरह का नशा कर रहे हैं, उसमें मदिरा और कच्ची शराब पुरानी चीजें हो गई हैं। अब हुक्का बार और अन्य मादक पदार्थों के सेवन के मामले देखे जा रहे हैं। सिंथेटिक नशे का दौर आ गया लगता है। गौरतलब है कि नशे का कारोबार इतना बड़ा हो गया है कि किसी भी राज्य में नशे का धंधा करने वाले या इस व्यापार के सूत्रधार देश के सुदूर कोने या विदेश में भी मिल सकते हैं।

अब तो ड्रोन से भी नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। हाल यह कि स्कूलों और कालेजों तक नशीले पदार्थ पहुंच रहे हैं। युवा पीढ़ी असमय बूढ़ी हो रही है, क्योंकि देश ने उसे सस्ता या मुफ्त राशन देकर भूख से न मरने देने की गारंटी तो दे दी, लेकिन रोजगार की नहीं। देश गर्व से फूला नहीं समाता कि हम डिजिटल हो गए। साइबर क्रांति हो गई। मगर स्याह तस्वीर तो यह है कि देश के युवा बेरोजगार हैं और नशे में डूब रहे हैं।

हम रोबोट युग की कल्पना कर रहे हैं, मगर सपने साकार करने वाली वह पीढ़ी ही तैयार नहीं कर रहे। इससे पहले युवा पीढ़ी पलायनवादी हो गई थी और डालर और पाउंड के मोह में सात समंदर पार जाकर करोड़पति हो जाना चाहती थी। राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप के 'अमेरिका प्रथम' के नारे के बाद जब सभी समृद्ध देशों ने यही नीति अपना ली, तो हमारे युवा स्वदेश लौटने लगे। मगर उनके सपने धुंधले पड़ गए, क्योंकि यहां उनके लिए नौकरी नहीं थी।

हालांकि रेवड़ियां बांटने से राजनीतिक दलों को फुर्सत नहीं है। उनके चुनावी एजंडे में रोजगार नहीं है। दूसरी ओर, बिना काम किए खाते में पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी कहां जाए? निराश होकर युवा नशे में डूब रहे हैं। दूसरी ओर, व्यवसायियों ने एक के बाद एक विश्वविद्यालय परिसर तो खड़े कर दिए, लेकिन पुस्तक संस्कृति धीरे-धीरे लुप्त हो गई। जहां तक हमारे पाठ्यक्रमों, अध्यापन और शोध का संबंध है, उसमें वह परिवर्तन नहीं आया जो इस तेजी से बदलते हुए युग की कल्पना करने वाले देश में आना चाहिए था। सवाल है कि इस बीच नशीले पदार्थों का कारोबार कैसे खड़ा हो गया? युवा कहे जाने वाले इस देश में बड़ी संख्या में नौजवान नशे की गिरफ्त में क्यों नजर आते हैं?

स्थिति यह है कि नशे के शिकार युवाओं की मौत की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। देश के सरहदी इलाकों में नशे का प्रसार खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जब सरहद पर दुश्मन खड़े हों और मुकाबला करने वाली युवा पीढ़ी नशे की कंदराओं में भटक रही हो, तो इसका क्या परिणाम होगा, इसे समझा जा सकता है। कभी सोचा भी नहीं गया था कि देश के कुछ नागरिक चंद पैसे के लिए शत्रु देशों के लिए जासूसी करेंगे और इसकी आड़ में वे नशे का कारोबार भी खड़ा कर लेंगे। कौन-सा राज्य इससे बचा है? यह किसी से छिपा नहीं है कि सरहदी राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में नशाखोरी बढ़ी है। तमाम अभियानों के बावजूद नशीले पदार्थों के तस्कर यहां पांव पसार रहे हैं। इन राज्यों में नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है।

हैरत की बात है कि कुछ माफिया नशे का कारोबार फैला कर इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि वे देश की राजनीति को संचालित करने का सपना देखने लगते हैं। इन समस्याओं का समाधान बुलडोजर संस्कृति नहीं है। दुखद है कि अब यह संस्कृति हरियाणा और पंजाब में भी दिख रही है। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अब मानवीय मूल्यों को बचाने की जद्दोजहद भी सामने आ रही है। अभी पिछले दिनों पंजाब के गांव नंगल कलां में एक नई तस्वीर नजर आई। यहां नशे के शिकार एक युवक की मौत हो गई।

हालांकि ऐसी घटनाएं पहले भी हुईं और मां-बाप इसे अपनी किस्मत मान कर चुप बैठ गए। मगर अब लोग विरोध में आगे आ रहे हैं। एक नौजवान नशे के कारण इस गांव में मरा, तो उसके परिजनों ने गांव के एक परिवार पर नशीले पदार्थ बेचने का आरोप लगा कर अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया। नई बात यह थी कि यहां पंचायत जागी। उसने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी परिवार को गांव से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। उनकी संपत्ति ढहाने के लिए दबाव बनाया साथ ही यह कह दिया कि अगर पुलिस और प्रशासन यह कार्रवाई नहीं करते, तो ग्रामीण खुद यह कदम उठाएंगे।

पंजाब में नशाखोरी के खिलाफ पिछले एक वर्ष से अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने छापे मार कर सैकड़ों तस्कर पकड़े हैं। इनमें से बहुत सारे आरोपियों को सजा भी दिलवाई है। हजारों किलो नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। मगर समस्या दूर नहीं हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 2025 में नशाखोरी से चौदह लोगों की जान गई। यह हालत केवल पंजाब की ही नहीं, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की भी है। लोगों ने घरों में अवैध शराब की भट्ठियां लगा रखी हैं।

ऐसे में अवैध शराब का धंधा खूब फल-फूल रहा है। पिछले दिनों पंजाब में यह आवाज उठती रही कि राज्य में अफीम की वैध खेती करने की इजाजत दे दी जाए। यह इजाजत नहीं दी गई, लेकिन अफीम और भुक्की (चूरा पोस्त) बड़े पैमाने पर पंजाब में बिकती है। चिट्टा खाकर नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। यह एक प्रकार का सिंथेटिक नशा है। इसे गंभीरता से लेना होगा। मंचों पर भाषण देने से जन जागरण नहीं होगा।

पंजाब में नशाखोरी की समस्या बहुत भयावह हो गई है। इसलिए मानसा जिले के नंगल कलां में ही नहीं, अन्य जिलों में भी लोग अपने बच्चों को नशे के चंगुल में जाते देख कर आवाज उठाने लगे हैं। यह आंकड़ा भी सामने है कि पंजाब के करीब 4500 गांवों ने खुद को 'नशामुक्त' घोषित कर दिया है। इसका कारण यह है कि गांवों में पढ़े-लिखे लोगों के साथ पंचायतें भी सक्रिय हो रही हैं। बेहतर तो यही होगा कि जागरूक नागरिक नशीले पदार्थों का काला कारोबार होता देखें, तो उसके खिलाफ सामूहिक रूप से आवाज उठाएं और प्रशासन को सूचित करें। यह बात किताबी लगती है, लेकिन पंजाब में इसमें थोड़ी सफलता दिखी है। यह छोटी ही सही, लेकिन सार्थक आवाज होगी।

जब हम नए युग की कल्पना करते हैं, तो उसमें प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व के साथ नागरिकों को भी एकजुट होना चाहिए। यह समस्या चूंकि हर राज्य में गंभीर होती जा रही है, तो जरूरी है कि कहीं से आवाज उठे, कोई सार्थक पहल हो। गंभीरता से कार्रवाई हो, तो नशाखोरी खत्म होते देर नहीं लगेगी। इसके लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिबद्धता तथा दूसरे जनसमूहों की ईमानदारी से पहल। ऐसा अभी तक संभव नहीं हुआ, लेकिन अगर कहीं भी जन-जागरण होता है, तो यह अपने आप में आशा की एक किरण है।

काशी में विक्रमोत्सव- संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण

भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र यदि किसी नगर को कहा जाए तो वह निस्संदेह काशी है। ऐसी पवित्र और ऐतिहासिक नगरी में जब सम्राट विक्रमादित्य की परंपरा को पुनर्जीवित करने वाला विक्रमोत्सव आयोजित होता है, तो वह मात्र एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय आत्मा के पुनर्जागरण का सशक्त माध्यम बन जाता है।

हाल ही में काशी में आयोजित विक्रमोत्सव ने इसी भावना को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। इस आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की सांस्कृतिक धारा केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाली जीवंत शक्ति है। इस भव्य आयोजन में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सक्रिय भूमिका और पहल ने इसे विशेष महत्व प्रदान किया।

विक्रमोत्सव के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के शासन, न्याय व्यवस्था और सांस्कृतिक योगदान को जिस भव्यता के साथ प्रस्तुत किया गया, उसने यह संदेश दिया कि भारत के इतिहास में निहित आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। इस आयोजन में प्रस्तुत महानाट्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने हजारों दर्शकों को भारतीय परंपरा और गौरव से जोड़ने का कार्य किया।

इस अवसर पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ङ्घशद्दद्ब, स्त्रद्बह्ल4ड्ढठ्ठड्ढह्लद्ध की उपस्थिति और उनके वक्तव्य ने इस आयोजन के महत्व को और बढ़ा दिया। उन्होंने जिस प्रकार डॉ. मोहन यादव के प्रयासों की सराहना की, वह केवल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह उस विचारधारा की स्वीकृति थी, जिसमें संस्कृति को शासन और समाज के केंद्र में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि भारत को अपने नायकों, अपनी परंपराओं और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना चाहिए, और उन्हें जन-जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है।

काशी में विक्रमोत्सव का आयोजन वास्तव में ÷एक भारतङ्कश्रेष्ठ भारत÷ की अवधारणा को साकार करने का उदाहरण भी बना। मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा और उत्तरप्रदेश की आध्यात्मिक धारा का यह संगम एक व्यापक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनकर सामने आया। उज्जैन और काशी—दोनों ही भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के प्रमुख केंद्र रहे हैं, और इन दोनों के बीच स्थापित यह सांस्कृतिक सेतु भविष्य में और भी सशक्त हो सकता है।

इस आयोजन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता रही काशी विश्वनाथ धाम में वैदिक घड़ी की स्थापना। यह केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि भारतीय कालगणना और ज्ञान परंपरा के पुनर्स्मरण का प्रतीक है। यह प्रयास इस बात का संकेत देता है कि आधुनिकता के साथ-साथ अपनी परंपराओं को भी समान महत्व दिया जा सकता है।

विक्रमोत्सव के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि भारत का इतिहास केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे जीवंत अनुभव के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य जैसे महान शासकों के आदर्शों को पुनर्स्थापित कर आज की पीढ़ी को प्रेरित किया जा सकता है।

निस्संदेह, काशी में आयोजित यह विक्रमोत्सव भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने यह सिद्ध किया है कि यदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को व्यापक दृष्टि और प्रभावी नेतृत्व के साथ आयोजित किया जाए, तो वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकते हैं।

अंततः यह कहा जा सकता है कि काशी में हुआ यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक संदेश है—एक ऐसा संदेश जो भारत को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए उसे भविष्य की ओर अग्रसर करता है। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि भारत की शक्ति उसकी संस्कृति में निहित है, और जब यह संस्कृति जागृत होती है, तो राष्ट की चेतना भी नई ऊर्जा से भर उठती है।

अत्याचार से आश्रय तक-उप्र में बांग्लादेशी हिंदुओं की नई शुरुआत क्यों देती है बड़ा संदेश

अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की लगभग 3100 घटनाएं दर्ज की गई हैं। घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, महिलाओं पर हमले हुए और कई निर्दोषों की जान चली गई। यह हिंसा कोई अलग घटना नहीं, बल्कि धार्मिक कट्टरता की निरंतर मुहिम है, जिसने बांग्लादेशी हिंदुओं को अपने ही देश में बेघर और असुरक्षित बना दिया है। इन्हीं अत्याचार की घटनाओं के बीच यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे निर्देश पर बांग्लादेश से आए 331 विस्थापित हिंदू परिवारों को स्थायी रूप से बसाया गया है।

(भावेश पाण्डेय)

यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे निर्देश पर बांग्लादेश से आए 331 विस्थापित हिंदू परिवारों को स्थायी रूप से बसाया गया है।पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। वहां हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार, उनके अधिकारों पर लगाई गई पाबंदियां और धार्मिक मान्यताओं पर लगातार प्रहार उन्हें नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर कर देते हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद स्थिति और बिगड़ गई है।

अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की लगभग 3100 घटनाएं दर्ज की गई हैं। घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, महिलाओं पर हमले हुए और कई निर्दोषों की जान चली गई। यह हिंसा कोई अलग घटना नहीं, बल्कि धार्मिक कट्टरता की निरंतर मुहिम है, जिसने बांग्लादेशी हिंदुओं को अपने ही देश में बेघर और असुरक्षित बना दिया है।

इन्हीं अत्याचार की घटनाओं के बीच यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे निर्देश पर बांग्लादेश से आए 331 विस्थापित हिंदू परिवारों को स्थायी रूप से बसाया गया है।

हालांकि ये 331 परिवार हाल के वर्षों में नहीं आए हैं। ये परिवार 1960 से 1975 के बीच पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से धार्मिक अत्याचार, दंगे और अस्थिरता से बचकर भारत आए थे। उस समय ये परिवार लखीमपुर खीरी समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बस गए थे। उनका प्रारंभिक पुनर्वास वर्षों पहले हो चुका था, लेकिन अब योगी सरकार ने उन्हें स्थायी बसावट, भूमि अधिकार और पूर्ण सम्मान प्रदान कर दिया है।

लखीमपुर खीरी में पुनर्वास का विस्तार- ये परिवार तीन तहसीलों के चार गांवों में बसाए गए हैं। धौरहरा तहसील के सुजानपुर गांव में 97 परिवारों को बसाया गया है। मोहम्मदी तहसील के मोहनपुर ग्रन्ट गांव में 41 परिवारों को जगह दी गई है। मोहम्मदी तहसील के मियांपुर गांव में सबसे अधिक 156 परिवार बसाए गए हैं। गोला तहसील के ग्रन्ट नंबर-3 में 37 परिवारों को बसाया गया है। कुल मिलाकर इन चार गांवों में 331 परिवारों का पुनर्वास किया गया है।

स्थायी बसाव और सरकारी योजनाओं का लाभ- ये परिवार वर्षों पहले अस्थायी रूप से बसाए गए थे, लेकिन अब योगी सरकार ने उन्हें स्थायी पुनर्वास प्रदान कर दिया है। हर परिवार को खेतीबाड़ी के लिए कृषि भूमि आवंटित की गई है। साथ ही, पात्रता के आधार पर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का

लाभ भी दिया जा रहा है। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शामिल हैं।

बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान- इन परिवारों को बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। राशन वितरण, टीकाकरण, विकसित भारत जी-राम-जी के तहत रोजगार, स्कूलों में मिड-डे मील, समग्र शिक्षा योजना, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से इन गांवों में सड़क, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह केवल राहत नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ नई जिंदगी की शुरुआत है।

विस्थापित परिवारों की खुशी और आभार

नए पुनर्वास से इन परिवारों के चेहरे खिल उठे हैं। वे खुले मन से योगी सरकार का आभार जता रहे हैं। कई परिवारों का कहना है कि बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर जो जख्म उन्हें लगे थे, उन्हें योगी सरकार ने सुविधा, सुरक्षा और सम्मान देकर नर्क से बाहर निकाला है। दशकों तक अनिश्चितता और भय में जीने के बाद उन्हें अब अपना खेत, अपना घर और अपने बच्चों का उज्ज्वल भविष्य नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की सभ्यतागत सोच

यह पहल योगी आदित्यनाथ की सोच को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। उन्होंने बार-बार कहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना और संकट के समय में उनका समर्थन करना हर भारतीय का नैतिक कर्तव्य है। उनका प्रसिद्ध नारा 'बटेंगे तो कटेंगे' इसी एकता और सजगता का संदेश देता है। दुनिया में शायद ही कोई अन्य देश हो जो धार्मिक अत्याचार से पीड़ित हिंदुओं के लिए बांहें फैलाकर स्वागत के लिए तैयार हो। लखीमपुर खीरी का यह मॉडल उसी सभ्यतागत जिम्मेदारी का व्यावहारिक रूप है।

भारत हर हिंदू का आश्रयस्थल- बांग्लादेश में आज भी हिंदू परिवारों पर हमले जारी हैं, मंदिरों की तोड़फोड़ हो रही है और अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इन विस्थापितों को जमीन, योजनाओं और सम्मान देकर एक मजबूत संदेश दे रही है-भारत हिंदू पीड़ितों के लिए आश्रय स्थल है।भले ही आलोचक इसे राजनीतिक कदम कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन परिवारों को वोट बैंक नहीं, बल्कि आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक एकीकरण का आधार दिया जा रहा है। खेती की जमीन, ऋष्टा सुविधा, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं-ये सब वे चीजें हैं जो बांग्लादेश में उन्हें व्यवस्थित रूप से छीनी गई थीं।

भविष्य के लिए मिसाल- लखीमपुर खीरी में बांग्लादेशी हिंदुओं का पुनर्वास केवल एक स्थानीय प्रशासनिक कार्य नहीं है। यह सभ्यतागत जिम्मेदारी का जीवंत उदाहरण है। यह याद दिलाता है कि हिंदू-बहुल भारत की पहचान के साथ-साथ अपने सभ्यतागत बंधुओं की रक्षा करना भी उसकी नैतिक जिम्मेदारी है।

जब तक योगी सरकार अवैध घुसपैठ पर सख्ती और सच्चे शरणार्थियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाएगी, तब तक पड़ोसी देशों से आने वाले पीड़ित हिंदुओं को उम्मीद बनी रहेगी। लखीमपुर खीरी के गांवों में अब जो परिवार अपने खेतों में काम कर रहे हैं, उनके लिए अत्याचार की लंबी रात खत्म हो चुकी है और सम्मानजनक भविष्य की सुबह शुरू हो गई है।लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं। राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों पर निरंतर लेखन करते हैं। इस लेख में लेखक के निजी विचार हैं।

कलेक्टर-सीईओ के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण हुआ पक्की नाली का कार्य! महात्मा गाँधी रोजगार गरंटी योजना से किसानो के खेतो को मिलेगा जीवनदान!

ग्राम पंचायत खुरदरहा में उत्कृष्ट निर्माण तकनीकी टीम और सरपंच की मेहनत लाई रंग!

सरसींवा (सारंगढ़-बिलाईगढ़)/मूक पत्रिका

जनपद पंचायत बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत खुरदरहा (आश्रित ग्रामङ्कोदोपाली) में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कलेक्टर डॉ. संजय कनौजे एवं जिला पंचायत सीईओ इन्द्रजीत बर्मन के मार्गदर्शन में लगभग 18.91 लाख रुपये की लागत से रामायण खेत से छत्तर खेत तक पक्की नाली निर्माण कार्य स्वीकृत होकर सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया जो अब ग्रामीणों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहा है। ग्राम पंचायत एवं तकनीकी सहायक लिकेश कुमार के नेतृत्व में यह निर्माण कार्य गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए कराया गया। कार्य में तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखा गया जिससे नाली मजबूत, टिकाऊ और उपयोगी बनी है। इस पक्की नाली के निर्माण से अब जंगल से आने वाला पानी सीधे नाली के माध्यम से किसानों के खेतों तक आसानी से पहुंच सकेगा जिससे लगभग 15 से 20 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। पहले जहां किसानों को धान की फसल के दौरान पानी की कमी से जूझना पड़ता था वहीं अब इस समस्या का स्थायी समाधान हो गया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी और संतोष का वातावरण है। तकनीकी सहायक लिकेश कुमार ने बताया कि यह कार्य कलेक्टर एवं जिला सीईओ के मार्गदर्शन अनुसार पूरी गुणवत्ता के साथ कराया गया है। उन्होंने विशेष रूप से एपीओ शशिकांत गुप्ता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निर्देशानुसार कार्य स्थल का चयन उपयोगिता के आधार पर किया गया। साथ ही छ्रक्र्र स्क्र एवं क्काङ्क्ष, क्क जैसे आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग कर सटीक स्थान चिन्हांकन किया गया, जिससे कार्य की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सकी। इस कार्य की सफलता में ग्राम पंचायत, सरपंच एवं पूरी टीम की सक्रिय भागीदारी और समन्वय सराहनीय रहा। सभी के सामूहिक प्रयास से यह निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण हुआ, जो ग्रामीण विकास की दिशा में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रशासनिक अधिकारियों के कुशल नेतृत्व और तकनीकी टीम की मेहनत से यह कार्य न केवल रोजगार सृजन का माध्यम बना बल्कि गांव की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिसकी ग्रामीणों द्वारा खुलकर प्रशंसा की जा रही है।

बरमकेला सहकारी समिति केंद्र में हुआ सरसों खरीदी का शुभारंभ पीएम आशा योजना से किसानों को मिल रहा समर्थन मूल्य का लाभ

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएम आशा) योजना के तहत बरमकेला सहकारी सेवा समिति में सरसों (सीजी-2 वैरायटी) की खरीदी का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय नायक, सदस्य अभिलाषा नायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पूजा-अर्चना कर खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत किया। इस अवसर पर उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव उपस्थित थे।बरमकेला क्षेत्र में रबी सीजन के दौरान बड़े पैमाने पर सरसों की खेती की जाती है। इस वर्ष लगभग 800 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किसानों ने सरसों की फसल ली है। शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 6200 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। ग्राम झाबड़ के किसान रामकुमार नायक ने बताया कि उन्होंने इस रबी सीजन में 10 एकड़ जमीन में सरसों की खेती की है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदी शुरू होने से उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है। किसान ने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताया। क्षेत्र में सरसों के साथ-साथ चना और मसूर की भी खेती की जाती है, लेकिन बरमकेला ब्लॉक में सरसों का रकबा अधिक है। औसतन प्रति हेक्टेयर लगभग 5 क्विंटल उत्पादन हो रहा है। मंडी में कुल मिलाकर लगभग 6200 क्विंटल सरसों की खरीदी की जा रही है। यह खरीदी जिले की विभिन्न प्राथमिक सेवा सहकारी समितियों–दानसरा, अमझर, नवरंगपुर, सहसपुर, बरमकेला, गोबरसिंघा, बार और भटगांव के माध्यम से की जा रही है।सरकार की इस पहल से क्षेत्र के किसानों में उत्साह है और उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा है।

बनरांका में तहसील स्तरीय कर्मा जयंती में उपमुख्यमंत्री साव होंगे शामिल

बेमेतरा/मूक पत्रिका

ग्राम बनरांका में ग्रामीण परिक्षेत्र व तहसील साहू संघ थानखम्हरिया के संयुक्त तत्वाधान में 12 अप्रेल दिन रविवार को तहसील स्तरीय भक्त माता कर्मा महोत्सव, शपथ ग्रहण और सामाजिक आदर्श विवाह ,एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है।

इस आयोजन के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव होंगे। उक्त कार्यक्रम का अध्यक्षता साजा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ईश्वर साहू करेंगे और प्रमुख अतिथि के रूप में दीपेश साहू जी विधायक बेमेतरा, और जितेन्द्र साहू (अध्यक्ष तेलघानी बोर्ड छ. ग. शासन),और दीपक ताराचंद साहू (पूर्व अध्यक्ष हस्तशिल्प बोर्ड छ. ग.) अतिविशिष्ट अतिथि के रुप में नारद साहू (अध्यक्ष जिला साहू संघ बेमेतरा), गैंदराम साहू (पूर्व अध्यक्ष जिला साहू संघ बेमेतरा), रामकुमार साहू (पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश साहू संघ छ. ग.) और विशिष्ट अतिथि के रुप में अजय साहू (जिला भाजपा बेमेतरा), जितेन्द्र साहू (अध्यक्ष जनपद पंचायत साजा), हेमसिंह साहू (अध्यक्ष तहसील साहू संघ देवकर), गौकरण साहू (अध्यक्ष तहसील साहू संघ साजा), मोहित साहू (अध्यक्ष तहसील साहू संघ दाढ़ी), अमर दास (अध्यक्ष तहसील साहू संघ धमधा), लक्ष्मी साहू (म. सयो.जिला साहू संघ, बेमेतरा), परिक्षेत्र अतिथि रामजी साहू, गिरधर साहू, अंतराम साहू, युवराज साहू तथा तहसील के सभी पदाधिकारी और तहसील साहू संघ थानखम्हरिया के अन्तर्गत आने वाले सभी गाँव के ग्रामीण पदाधिकारी और सभी प्रकोष्ट पदाधिकारी और ग्राम पंचायत बनरांका के समस्त ग्राम उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम विवरण क् शोभा यात्रा सुबह 8:00 बजे अतिथि आगमन 12 बजे से , उद्बोधन दोपहर 1 बजे से, भोजन भंडारा 2 बजे से वर- वधु आशीर्वाद 5 बजे से

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत फिल्म स्टार तारा साहू की अनुपम प्रस्तुति रंग तरंग छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 10 से बजे प्रारंभ होगा। उक्त जानकारी तहसील साहू संघ थानखम्हरिया के अध्यक्ष बसंत साहू और युवा प्रकोष्ट के संयोजक रमेश साहू ने दी ।

निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया अवलोकन, जल आवर्धन योजना में धीमी प्रगति, कलेक्टर ने ठेकेदार को लगाई फटकार

कलेक्टर जल आवर्धन योजना का किया निरीक्षण

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जिले में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने नगरीय निकाय शिवरीनारायण एवं खरौद में निर्माणाधीन जल आवर्धन योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर दोनों नगरीय क्षेत्रों में महानदी से शुद्ध एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ओवरहेड टैंक निर्माण, पाइपलाइन विस्तार, जल स्रोत से कनेक्टिविटी तथा अन्य तकनीकी कार्यों की प्रगति का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं तथा गुणवत्ता के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। खरौद में निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने ठेकेदार के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य में तत्काल गति लाई जाए, अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर कलेक्टर ने जल जीवन मिशन अंतर्गत पामगढ़ समूह जल प्रदाय योजना के तहत निर्माणाधीन जल शुद्धिकरण संयंत्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संयंत्र की कार्यप्रणाली, निर्माण गुणवत्ता तथा प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कर आमजन को लाभान्वित किया जा सके।कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा किसी भी प्रकार की बाधा को समय रहते दूर कर कार्यों को गति प्रदान की जाए। कलेक्टर द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जिले में संचालित सभी निर्माण कार्यों की सतत निगरानी की जा रही है और समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 हेतु मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 के लिए निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष के रिक्त पद के निर्वाचन तथा त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत जनपद पंचायत सदस्य (बेरला) के 01 पद, सरपंच के 02 पद तथा पंच के 21 रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन कराए जाएंगे। निर्वाचन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्रों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। इसके अंतर्गत निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 13 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। इसके बाद मतदाताओं से दावा एवं आपत्तियां 20 अप्रैल 2026 को अपरान्ह 3 बजे तक प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावा-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। इसके अलावा प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2026 रखी गई है। वहीं प्रारूप क-1 में प्राप्त दावों के निराकरण की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2026 तय की गई है 7 दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद पारित आदेश के विरुद्ध अपील आदेश पारित होने के पांच दिनों के भीतर की जा सकेगी। सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 05 मई 2026 को किया जाएगा।

बरमकेला धान संग्रहण केंद्र का कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

धान की गुणवत्ता, भंडारण और सीसीटीवी की स्थिति का कलेक्टर ने किया भौतिक अवलोकन

धान के शीघ्र उठाव के निर्देश, स्टैक में 40 किलो प्रति बोरी पाया गया वजन

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने बरमकेला धान संग्रहण केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संग्रहण केंद्र में रखे धान की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच की। उन्होंने सबसे पहले केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की जानकारी ली और यह सुनिश्चित किया कि निगरानी व्यवस्था सुचारु रूप से चालू हो रही है या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने धान के भंडारण की स्थिति का अवलोकन करते हुए देखा कि आकस्मिक बरसात से कहीं धान को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचा है। कलेक्टर ने विशेष रूप से धान के स्टैक (भंडारण ढेर) का निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि धान को सही तरीके से ढककर रखा गया है या नहीं, ताकि बारिश, नमी या अन्य कारणों से फसल को नुकसान न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाएं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्टैक में रखे धान का वजन भी कराया, जिसमें प्रति बोरी लगभग 40 किलोग्राम वजन पाया गया। इस पर उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि मानक के अनुरूप भंडारण और तौल प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संग्रहित धान का उठाव शीघ्रता से किया जाए, ताकि लंबे समय तक भंडारण के कारण किसी प्रकार का नुकसान न हो। उन्होंने यह भी कहा कि उठाव कार्य में अनावश्यक विलंब न किया जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण की जाए।

खरसिया के बिंजकोट में प्लांटेशन में लाखों खर्च, वन विभाग ने रोपे पौधे, मौके पर मिले ठूंठ

रायगढ/मूक पत्रिका

वन मंत्री जब सदन में कहते हैं कि वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण का सर्वाइवल रेट 96 प्रश है तो लगता है यह तो बहुत अधिक है। हकीकत में दिया तले अंधेरा वाली स्थिति है। खरसिया के बिंजकोट में पौधे रोपे गए थे, लेकिन वहां कुछ ठूंठ ही दिखते हैं। वन विभाग क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, कैम्पा मद से वृक्षारोपण करता है। हर साल करोड़ों रुपए प्रदेश में केवल वृक्षारोपण पर ही खर्च किए जाते हैं। वर्ष 25-26 में प्रदेश में कैम्पा मद से 537 करोड़ के काम करने की मंजूरी मिली है। इतनी रकम में तो प्रदेश के कई जिलों को हरा-भरा किया जा सकता है। सोचिए कि हर साल इतने करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन इस रकम से जमीन तो नहीं लेकिन अफसर हरे-भरे हो रहे हैं। खरसिया के बिंजकोट में वन विभाग ने सैकड़ों पौधे लगाने का दावा किया है। क्षेत्र को हरा-भरा करने के लिए लगाए गए पौधे नजर नहीं आ रहे हैं। वहां कुछ ठूंठ ही दिख रहे हैं। कागजों में प्लांटेशन किया गया है। फर्जी बिल वाउचर बनाकर गड़बड़ी की गई है। अब मामला खुल रहा है तो जेसीबी लगाकर गड्ढे खोदे जा रहे हैं। बोर खनन भी कराया जा रहा है।

पौधरोपण का कोई हिसाब नहीं

बीते सालों में जितने पौधे वन विभाग ने लगाए हैं, उनका सर्वाइवल रेट जानने के लिए भौतिक सत्यापन ही नहीं किया जाता। कितने पौधे कहां रोपे गए, कितना खर्च हुआ, कितने जीवित हैं, इसकी जांच हुई तो बड़े राज खुलेंगे। जितने पौधे लगाए जा चुके हैं, उससे तो आधा रायगढ़ जंगल बन चुका होता।

तिलमिलाए कुछ सरपंचों और सचिवों का कारनामा

भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकारो व आरटीआई कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में घेरने की कोशिश....

रायगढ/मूक पत्रिका

भ्रष्टाचार उजागर होने से तिलमिलाए जिला सरपंच संघ रायगढ़ अब झूठे आरोप लगाकर मीडिया को डराने की कोशिश की जा रही है। डराने धमकाने का यह खेल वही सरपंच और सचिव कर रहे हैं, जिनकी करतूतों को ह्लद्ब कार्यकर्ताओं व मीडियाकर्मियों ने उजागर किया था। पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार का खुला खेल खेलने वाले जिला सरपंच संघ रायगढ़ के निशाने पर अब ह्लद्ब कार्यकर्ता व पत्रकार आ गए हैं।राज्य की भाजपा सरकार को बदनाम करने का कुचक्र रचने वाले जिला सरपंच संघ ने राष्ट्रीय सूचना जन सूचना आयोग दिल्ली भारत सरकार, राज्य सूचना आयोग नया रायपुर, जिला सूचना आयोग जिला रायगढ़ के पास शिकायती पत्र भेजकर नया पैतरा चला है।

दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता आरटीआई के माध्यम से ग्राम पंचायतो से जानकारी निकाल कर - ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों के नाम पर हो रही धांधली, बिना कोई कार्य कराए ही पूरी राशि आहरित कर ली जाने, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का जरा भी ध्यान न रखे जाने, कई पंचायत सचिवों के एक ही जगह पर सालों से पदस्थ रहने, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ग्रामीणों से रकम मांगने आदि की खबरें पत्रकार लगातार प्रकाशित कर प्रशासन और शासन का ध्यान आकर्षित कराते रहे हैं। ऐसे में तिलमिलाहट लाजिमी है। इसी तिलमिलाहट के चलते आज जिला सरपंच संघ रायगढ़ ने जन सूचना आयोग दिल्ली भारत सरकार, राज्य सूचना आयोग नया रायपुर, जिला सूचना आयोग जिला रायगढ़ के पास ह्लद्ब कार्यकर्ताओं व पत्रकारों के खिलाफ झूठी शिकायत कर दी है। इस साजिश में वो कई सरपंचे भी शामिल हैं, जो लगातार अपनी पंचायत में विकास एवं निर्माण कार्यों में अनियमितता बरत रहे थे। उनके खिलाफ भी समाचार खबर प्रकाशित करते रहे हैं जिससे अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए ने जिला सरपंच संघ ने शिकायत का सहारा लिया है। कुछ सफेदपोश नेताओं की शह पर ही ह्लद्ब कार्यकर्ताओं व मीडिया को बदनाम करने का कुचक्र इन भ्रष्ट सरपंच द्वारा किया जा रहा है।

कुछ सरपंचों के इशारे पर ही जिला सरपंच संघ रायगढ़ ने झूठी शिकायत का सहारा लिया है।-वर्तमान व पूर्व कार्यकाल के दौरान जनपदो के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में सरकारी धन की जमकर बंदरबांट हुई है। सारे निर्माण कार्य दिखावे के लिए किए गए हैं। इन कार्यो की वृहद जांच कराई गई तो बड़ा घोटाला उजागर होगा। वहीं रायगढ़ जिले के कई ब्लॉको के जनपद के पंचायत सचिव की ठेकेदारी भी सुर्खियों में रही है। कई सरपंच व सचिव महाशय अपने परिवार के एक सदस्य के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं और प्रायः सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों का ठेका इसी कंपनी को मिलता है। ये सारे खुलासे व अपने बचाव के लिए शिकायत की गई है ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आरटीआई (ऋञ्जढ्ढ) कार्यकर्ताओं व पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी मांगने पर विकास कार्यों की फाइलें गायब कर देते हैं कई पंचायतो मे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन लगाया जाता है। लेकिन जन सूचना अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार उजागर होने के डर से आरटीआई कार्यकर्ता को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है जब सरपंच सचिव दूध के धुले हैं वह पंचायत में सरपंच सचिव के द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई है तो सचिव जानकारी देने में कतराते क्यों है जिले में जन सूचना अधिकार अधिनियम का अफसर मखौल उड़ा रहे हैं। सरकारी विभागों से मांगी गई जन सूचना उपलब्ध कराने में खूब मनमानी की जा रही है। आधी-अधूरी सूचना देकर अफसर कोरम पूरा कर लेते हैं। जिससे जन सूचनाकर्ता को समय के साथ अतिरिक्त शुल्क खर्च करना पड़ता है। सूचना न मिलने से विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार भी उजागर नहीं हो पाता है। सूत्र की मानें तो आरटीआइ दाखिल होने पर घोटालों की परत दर परत खुलने का भय अफसरों को सताने लगता है। यही कारण है कि आरटीआइ देने से अफसर कतराते हैं भ्रष्टाचार उजागर होने के डर से जिला सरपंच संघ द्वारा कई आरटीआई कार्यकर्ता व पत्रकारों को निशाने में लिया गया है और उनके खिलाफ झूठे शिकायत की गई है.

समाज के लिए गंभीर संकेत: यह मामला केवल rti कार्यकर्ताओं व पत्रकार की छवि धूमिल करने का नहीं, बल्कि उन सभी आवाजों को दबाने का प्रयास है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई जाती हैं। यदि ऐसे मामलों पर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो सच्चाई के पक्ष में खड़े होने वाले लोग हतोत्साहित होंगे

संक्षिप्त समाचार

सैमसंग ने भारत में टॉप माउंट फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर्स तक बढ़ाया अपना बीस्पोक एआई लाइन-अप

गुरुग्राम। भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने अपने बीस्पोक एआई टॉप-माउंट फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर लाइन-अप के विस्तार की घोषणा की है। यह नई रेंज भारतीय घरों में समझदारी भरी बिजली बचत और आधुनिक लुक लाने के लिए तैयार की गई है। शानदार बीस्पोक डिज़ाइन वाले इन रेफ्रिज़रेटर्स में एडवांस एआई फीचर्स, स्मार्ट कनेक्टिविटी और भरोसेमंद परफॉरमेंस का बेहतरीन मेल है। रेफ्रिज़रेटर्स की इस नई रेंज में 256 लीटर और 236 लीटर की क्षमता वाले चुनिंदा मॉडल्स वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, ताकि इन्हें स्मार्टथिंग्स ऐप के ज़रिए स्मार्टफोन से आसानी से कंट्रोल और मॉनिटर किया जा सके। इन मॉडल्स में स्टाइलिश फ्लैट-डोर डिज़ाइन के साथ-साथ तुरंत कूलिंग के लिए पावर कूल और पावर फ्रीज जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इंडस्ट्री के बेहतरीन मानकों के साथ, ये रेफ्रिज़रेटर्स बिजली बचाने और शानदार परफॉरमेंस देने के लिए बनाए गए हैं। सैमसंग इंडिया के डिजिटल अप्लायंसेज़ बिज़नेस के वाइस प्रेसिडेंट घुफरान आलम ने कहा, भारत में सैमसंग के 30 साल पूरे होने के मौके पर, हम भारतीय ग्राहकों के लिए लगातार नए और बेहतर एनर्जी-एफिशिएंट समाधान ला रहे हैं। 300 लीटर से कम क्षमता वाले हमारे नए एआई-इनेबल्ड रेफ्रिज़रेटर्स, जिनमें बीस्पोक एआई टॉप माउंट फ्रीज़र भी शामिल है, भारतीय घरों में स्मार्टथिंग्स कनेक्टिविटी, मॉडर्न डिज़ाइन और बेहतर बिजली मैनेजमेंट की सुविधा देते हैं। यह एआई तकनीक को हर किसी तक पहुँचाने और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से समाधान देने की हमारी कोशिश को दर्शाता है। रेफ्रिज़रेटर की यह नई रेंज ग्राहकों को स्मार्टथिंग्स ऐप के ज़रिए फ्रिज की सेटिंग्स पर नज़र रखने और उन्हें बदलने की सुविधा देती है। इससे फ्रिज की कूलिंग और रोज़मर्रा के इस्तेमाल पर बेहतर कंट्रोल मिलता है, भले ही आप घर से दूर हों। उपकरण को लंबे समय तक दुरुस्त रखने के लिए स्मार्टथिंग्स होम केयर इसकी परफॉरमेंस की निगरानी करता है और कोई भी समस्या दिखने या किसी पुर्ज़े को बदलने की ज़रूरत होने पर यूज़र्स को अपने-आप अलर्ट भेज देता है।

रोबोटिक सर्जरी और रक्षा तकनीक में भारत की बड़ी उपलब्धि, एसएमआरएससी 2026 में 'प्रोजेक्ट विमाना' और 'प्रोजेक्ट ऑपेरियन' लॉन्च

नई दिल्ली: भारत में आयोजित तीसरे ग्लोबल एसएसआई मल्टी-स्पेशियल्टी रोबोटिक सर्जरी कॉन्फ्रेंस (SMRSC) 2026 के दौरान अत्याधुनिक चिकित्सा और रक्षा तकनीकों की ऐतिहासिक झलक देखने को मिली। इस अवसर पर एसएस इनोवेशंस इंटरनेशनल (SSII) ने दो क्रांतिकारी तकनीकों प्रोजेक्ट विमाना (Project Vimana) और प्रोजेक्ट ऑपेरियन (Project Operion) का अनावरण किया जो भविष्य की सर्जिकल और आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली को नई दिशा देने वाली मानी जा रही हैं। तीन दिवसीय इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के 1500 से अधिक डॉक्टरों और 250 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन में रोबोटिक सर्जरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेली-सर्जरी और मोबाइल ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर चर्चा की गई। इस दौरान एसएसआई मंत्रा-3 और मंत्रासन के माध्यम से 15 लाइव टेली- सर्जरी और 14 लाइव सर्जरी का सफल प्रदर्शन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर देश-दुनिया के कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञ जैसे डॉ. नरेश त्रेहान, डॉ. संगीता रेड्डी, डॉ. फ्रेडरिक मोल, श्री मधुसूदन साई और डॉ. मायलस्वामी अन्नादुरई भी मौजूद रहे।

सैमसंग के और गैलेक्सी डिवाइसेस पर मिलेगा वन यूआई 8 .5 बीटा प्रोग्राम

गुरुग्राम। सैमसंग अपने वन यूआई 8.5 बीटा प्रोग्राम का विस्तार और अधिक गैलेक्सी डिवाइसों तक कर रहा है। मार्च में वन यूआई 8.5 बीटा 1 के विस्तार के बाद, अब यह प्रोग्राम गैलेक्सी S23 सीरीज़, गैलेक्सी Z फोल्ड5, गैलेक्सी ̍ फ्लिप5, गैलेक्सी S23 FE और पहली बार ए-सीरीज़ के गैलेक्सी A36 5G सहित अन्य डिवाइसेस के लिए जारी किया जा रहा है। यह बीटा प्रोग्राम भारत, कोरिया, यूके और अमेरिका 2 जैसे चुनिंदा बाजारों में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध होगा। एंड्रॉइड के साथ अपने निरंतर सहयोग को आगे बढ़ाते हुए, सैमसंग वन यूआई 8.5 बीटा पर क्विक शेयर के माध्यम से एयरड्रॉप के लिए सपोर्ट पेश कर रहा है, जिससे गैलेक्सी S25 सीरीज़, गैलेक्सी S24 सीरीज़, गैलेक्सी Z फोल्ड7, गैलेक्सी Z फ्लिप7, गैलेक्सी Z फोल्ड6 और गैलेक्सी Z फ्लिप6 3 जैसे चुनिंदा डिवाइसेस के उपयोगकर्ताओं के लिए क्रॉस-प्लेटफॉर्म फाइल शेयरिंग अधिक सुगम हो जाएगी।

घरघोड़ा में कानून को ठेंगा मंत्री की सख्ती कागजों पर धरातल पर रसूखदारों की गिद्ध दृष्टि और उड़ती राख

मूक पत्रिका/ रायगढ़/ घरघोड़ा:- सरकारें विधानसभा के एसी कमरों में नियम बनाती हैं कसमें खाती हैं और दावों की झड़ी लगा देती हैं। लेकिन राजधानी से दूर जब धरातल की हकीकत देखी जाए तो नियम केवल फाइलों में दबे और रसूखदार उन पर नाचते नजर आते हैं। घरघोड़ा ब्लॉक के नावपारा टेड़ा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए खुलेआम फ्लाई ऐश का निपटान किया जा रहा है।?एक तरफ प्रदेश सरकार का संकल्प है कि भूमिहीन परिवारों को शासकीय भूमि आवंटित कर उन्हें खेती किसानी से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाए। लेकिन विडंबना देखिए जिन गरीब कंधों को सरकार सहारा दे रही है

उन्हीं की आवंटित कृषि भूमि पर अब उद्योगों के रसूखदारों और लिफ्टरों की गिद्ध जैसी नजर पड़ चुकी है। जिस जमीन पर धान की फसल लहलहानी चाहिए थी वहाँ अब जहरीली राख का ढेर लग रहा है।

मंत्री का मॉडल एस ओ पी हुआ फेल:- अभी हाल ही के विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देते हुए सीना ठोककर कहा था किसरकार जल्द ही मॉडल एसओपी के तहत ही फ्लाई ऐश का निपटान करने जा रहा है किंतु यह केवल कानों को सुनने तक सीमित रही आँखों को देखने के लिए नही। उन्होंने स्पष्ट किया था कि वन भूमि और कृषि भूमि पर राख डालना सख्त मना है। लेकिन घरघोड़ा की तस्वीरें मंत्री जी के दावों को मुँह चिढ़ा रही हैं। क्या प्रशासन मंत्री के निर्देशों को रद्दी का टुकड़ा समझता है।

अजब तहसीलदार गजब पटवारी सिस्टम की शतरंज- इस पूरे मामले में स्थानीय राजस्व अमले की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है।

नायब तहसीलदार का तर्क: घरघोड़ा नायब तहसीलदार का कहना है कि खसरा नंबर 311/4 पर पर्यावरण स्वीकृति के बाद काम हो रहा है। सवाल यह है कि क्या पर्यावरण विभाग ने कृषि भूमि को बंजर बनाने का लाइसेंस दे दिया है।

?पटवारी का बेचारा अंदाज पटवारी लोकेश पैकरा ने तो और भी कमाल की बात कही। उन्होंने माना कि भूमि पहले से कृषि भूमि है और आसपास खेती भी हो रही है लेकिन जांच प्रतिवेदन में ऐसा कोई कॉलम ही नहीं था जहाँ अगल-बगल की खेती का जिक्र किया जा सके।क्या अब नियमों का पालन सिर्फ कॉलम के भरोसे होगा अगर फॉर्म में कॉलम नहीं है तो क्या आँखों देखी हकीकत को दफ्न कर दिया जाएगा

जहरीली राख से किसका भला-फ्लाई ऐश का यह अवैध निपटान न केवल मिट्टी की उर्वरता खत्म कर रहा है बल्कि आसपास रहने वाले ग्रामीणों के फेफड़ों में जहर घोल रहा है। रसूखदारों की साठगांठ और अधिकारियों की तकनीकी चुप्पी ने गरीब किसानों को हाशिए पर धकेल दिया है।?अब देखना यह होगा कि विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें करने वाले जिम्मेदार इस फ्लाई ऐश कांड पर क्या एक्शन लेते हैं या फिर रसूखदारों का मैनेजमेंट इसी तरह नियमों का मखौल उड़ाता रहेगा।

बस्तर के विस्थापितों की घर वापसी से लेकर स्थानीय भर्ती तक, सर्व आदिवासी समाज ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

गोट्टी कोया पुनर्वास, DMFT संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, स्थानीय भर्ती, जेलों में बंद आदिवासियों की समीक्षा सहित कई मांगें उठाई गई

मूक पत्रिका/बीजापुर। सर्व आदिवासी समाज ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से शुक्रवार 10 अप्रैल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सलवा जुडूम के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विस्थापित हुए आदिवासी परिवारों की ससम्मान घर वापसी, स्वास्थ्य विभाग में डीएमएफटी के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, बस्तर-सरगुजा में स्थानीय भर्ती व्यवस्था बहाल करने सहित कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई गई हैं।

सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने बताया कि दक्षिण बस्तर के हजारों आदिवासी परिवार सलवा जुडूम और आंतरिक संघर्ष के दौरान अपना घर छोड़कर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में बस गए थे। वर्तमान में ये परिवार मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं और अपने पैतृक गांव लौटना चाहते हैं। सर्व आदिवासी समाज ने इन परिवारों का सर्वे कर सुरक्षित घर वापसी, पुनर्वास, भूमि आवंटन तथा वन अधिकार पत्र प्रदान करने की मांग की है। संगठन ने स्वास्थ्य विभाग में जिला खनिज संस्थान न्यास (छ्रस्न्नञ्ज) मद से कार्यरत संविदा कर्मियों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में कहा गया कि बस्तर जैसे दुर्गम क्षेत्र में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन सहित कई कर्मचारी वर्षों से कम मानदेय पर सेवाएं दे रहे हैं, जो समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत के विपरीत है। सर्व आदिवासी समाज ने संविदा भर्ती समाप्त कर नियमित नियुक्ति करने तथा वर्तमान कर्मियों का अनुभव के आधार पर नियमितीकरण करने की मांग की है।

इसके साथ ही बस्तर एवं सरगुजा संभाग में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर स्थानीय निवासियों की शत-प्रतिशत भर्ती व्यवस्था पुन: लागू करने की मांग भी की गई। ज्ञापन में कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय भाषा, संस्कृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

संगठन ने नक्सलवाद मुक्त बस्तर की घोषणा के बाद जेलों में बंद विचाराधीन आदिवासियों के मामलों की विधिक समीक्षा कर निर्दोषों की रिहाई हेतु विशेष नीति बनाने की मांग भी रखी। इसके लिए उच्चस्तरीय बस्तर शांति समीक्षा समिति गठन, विधिक सहायता और पुनर्स्थापन योजना लागू करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा बस्तर में चार दशकों से रहे नक्सलवाद के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। संगठन ने कहा कि स्थाई शांति के लिए समस्या की जड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है।

सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है।

ज्ञापन तहसीलदार बीजापुर पंचराम सलामे को सौंपा गया। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी, शंकर कुड़ियाम, कमलेश पैंकरा, सुशील हेमला, अमित कोरसा, कामेश्वर दुब्बा, मासा राम तेलाम, कार्तिक मांडवी, जितेंद्र हेमला, मानकुराम मरकाम, सुरेश कड़ती, हरिराम, मनीराम, लच्छिंदर हेमला, लक्ष्मण कड़ती, सतीश मांडवी, बचलू वाचम, पाकलु तेलम सहित बड़ी संख्या में समाज प्रमुख मौजूद थे।

14 अप्रैल 2026 को होगा ग्राम सभा का आयोजन

मूक पत्रिका/बीजापुर।- छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार 14 अप्रैल 2026 को आयोजित ग्रामसभा में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को कलेक्टर द्वारा निर्देश दिया है। जिसके अर्न्तगत ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन। पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की जाये। पिछली वर्ष में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाये। ग्राम पंचायतों में कर अधिरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली ऑनलाईन करने के लिए समर्थ पंचायत पोर्टल का उपयोग करने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर के दर निर्धारण पश्चात कर अधिरोपण प्रारंभ करना। पंचायतों के वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारी/ कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा/हिसाब लेना है अथवा बकाया राशि है, उनके नामों का वाचन। राज्य की समस्त सड़कों पर, मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषत: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गो) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना।

कांकेर पुलिस की अनूठी पहल: 'मोर मितान' के जरिए ग्रामीणों से सीधा संवाद, अपराध मुक्त समाज का संकल्प

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर /कांकेर:-उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत चलाए जा रहे 'मोर मितान' अभियान के अंतर्गत सतत जनसंवाद कार्यक्रम जारी है। पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम करने और अपराधों पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से थाना कोतवाली कांकेर के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी प्रतीक बनसोडे (भापुसे) के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम पंचायत कुष्ठिकुर, पीठापाल और बारदेवरी का दौरा किया। इस दौरान 'चलित थाना' के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और मौके पर ही उचित मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और युवा उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीके और साइबर हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। महिला सुरक्षा टीम की त्वरित कार्रवाई और हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग के बारे में बताया गया। साथ ही बाल विवाह और मानव तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की गई। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों के पालन के निर्देश दिए गए। नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए परिवार और समाज को इससे बचाने का आह्वान किया गया। गांव में आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों और किराएदारों की सूचना तत्काल पुलिस बीट आरक्षक को देने को कहा गया।

कांकेर पुलिस ने जनता से अपील की है कि अपराध नियंत्रण एक साझा जिम्मेदारी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी देने के लिए अपराधिक हेल्पलाइन नंबर 94791-55125 और महिला हेल्पलाइन नंबर 94791-55925 पर संपर्क किया जा सकता है। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इस अभियान में थाना प्रभारी प्रतीक बनसोडे के साथ बीट प्रभारी उपनिरीक्षक सुरेन्द्र मानिकपुरी, प्रधान आरक्षक 773 दिनेश कुलदीप, आरक्षक रामसेवक पैकरा और थाना पेट्रोलिंग टीम का विशेष योगदान रहा।

लोगों के लिए छलावा साबित हो रही मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना

मूक पत्रिका/चांपा। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना लोगों के लिए छलावा साबित हो रही है अधिकांश लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते लोग सरकार को कोसने मजबूर है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के शुरू होते ही लोगों के मन में भारी भरकम बिजली बिल से राहत मिलने की उम्मीद जगी थी लेकिन उनकी उम्मीद पर तब पानी फिर गया जब समाधान शिविर में जाकर कुछ लोगों ने अपने भारी भरकम बिजली बिल को कम कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कई तरह की समस्या बताकर चलता कर दिया गया।

चांपा शहर के एक उपभोक्ता ने बताया वह वार्ड में लगे समाधान शिविर में जाकर अपनी भारी भरकम बिजली बिल को कम कराने की कोशिश की, लेकिन पोर्टल में देखने पर पता चला कि उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए वह मायूस होकर सरकार को कोसने मजबूर है। इसी तरह और कई लोगों में समाधान शिविर में भारी भरकम बिजली बिल की राशि से राहत नहीं मिलने से नाराज है।

सबको नहीं मिल सकता योजना का लाभ - इस संबंध में विद्युत वितरण कंपनी जांजगीर-चांपा की डीई श्री भारद्वाज क्या करना है कि वर्ष 2023 को आधार मानकर बिजली बिल में राहत दी जा रही है इसके अलावा मोर बिजली एप के माध्यम से हितग्राही यह पता कर सकता है

कि उसे बिजली बिल में राहत मिलेगी या नहीं बाहर हाल योजना को लेकर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए सीख रही योजना का प्रचार प्राप्त किया जाएगा।

भारी भरकम बिजली बिल से परेशानी - छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के बाद खासकर बिजली बिल को लेकर लोग बेहद परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी मध्यम और निकले तबके के लोगों को हो रही है। लोगों का कहना है जब से स्मार्ट मीटर लगा है, तब से अनाप-शनाप बिजली बिल भेजा जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल आधी कर दी गई थी, जिसे लोगों को राहत मिल रही थी लेकिन मौजूदा सरकार लोगों को राहत देने के मूड में नहीं दिख रही है।

बालको की पहल से मूंगफली बनी किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम

कोरबा। कोरबा के आसपास के ग्रामीण इलाकों में खेती का तरीका धीरे-धीरे बदल रहा है। पहले किसान ज्यादा पानी वाली धान की खेती पर निर्भर थे, लेकिन अब वे मूंगफली की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) अपनी 'मोर जल मोर माटी' योजना के जरिए 40 गांवों के 9,000 से अधिक किसानों को सहयोग दे रही है। परियोजना के तहत जल प्रबंधन, आधुनिक खेती, पशुपालन, गैर-लकड़ी वन उत्पाद और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में बालको ने क्षेत्र के किसानों के बीच मूंगफली की खेती को एक लाभकारी विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया है। पहले क्षेत्र में बहुत कम किसान मूंगफली की खेती करते थे, वह भी केवल घरेलू उपयोग के लिए। पारंपरिक तरीकों के कारण लागत अधिक और उत्पादन कम होने से किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता था। साथ ही बाजार तक पहुंच की कमी भी एक बड़ी समस्या थी। बालको ने बेहतर बीज, खाद और तकनीकी मदद देकर इन समस्याओं को कम किया है। अब किसानों को लाइन से बुवाई, बीज उपचार और सही मात्रा में खाद देने जैसे तरीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उत्पादन बढ़ा है। कंपनी के सामुदायिक विकास प्रयासों का असर साफ दिखाई दे रहा है। पहले जहां 50 से भी कम किसान मूंगफली उगाते थे।

मुकुल चौधरी ने अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। उन्होंने 7 छक्के लगाए।

लखनऊ की IPL में लगातार दूसरी जीत, कोलकाता हारी

मुकुल चौधरी ने 27 बॉल पर नाबाद 54 रन बनाकर जिताया, आयुष बडोनी की फिफ्टी

कोलकाता। लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL-2026 में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। टीम ने गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हराया। टीम को आखिरी 18 बॉल पर 43 रन चाहिए थे और 7 विकेट गिर चुके थे। ऐसे में मुकुल चौधरी ने 27 बॉल पर नाबाद 54 रन की पारी खेलकर टीम को हारा हुआ मैच जिता दिया। ईडन गार्डन्स स्टेडियम में लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। कोलकाता ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 181 रन बनाए। 182 रन का टारगेट लखनऊ ने 20 ओवर में 7 विकेट पर हासिल कर लिया।

मुकुल चौधरी ने छक्का लगाकर मैच टाई कराया। उसके बाद बाई का एक रन दौ?कर टीम को जीत दिलाई। यहां विकेटकीपर अंगकृष रघुवंशी का थ्रो नहीं लगा।

ब्रीफ न्यूज

बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर नियमों को सख्त किया

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मुकाबलों में अनुशासन बनाये रखने के लिए सख्त नियम बनाये हैं।

नए नियम के तहत अब केवल वही 16 खिलाड़ी मैदान पर प्रवेश कर सकेंगे, जिनका नाम आधिकारिक टीम शीट में दर्ज होगा। इससे साफ है कि जो खिलाड़ी इस सूची में शामिल नहीं हैं, वे किसी भी स्थिति में मैदान पर कदम नहीं रख सकेंगे। ड्रिंक्स ले जाना,खिलाड़ियों तक रणनीतिक संदेश पहुंचाना, बैट या अन्य उपकरण मैदान में देना, इन सभी कार्यों पर अब प्रतिबंध रहेगा। यदि खिलाड़ी नामित 16 में शामिल नहीं है। इसके अलावा, बाउंड्री लाइन के आसपास मौजूद खिलाड़ियों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। अब एक समय में अधिकतम पांच खिलाड़ी ही बिब पहनकर बाउंड्री के पास रह सकते हैं। ये पांच खिलाड़ी नामित 16 में से भी हो सकते हैं या बाकी स्क्वॉड से, लेकिन संख्या पांच से अधिक नहीं होगी।

शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े गये वार्नर

सिडनी। ऑस्ट्रेलियाई के पूर्व क्रिकेट डेविड वार्नर एक बार विवादों में है। वार्न को सिडनी पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ा है। वार्नर संन्यास के बाद से ही लीग क्रिकेट में सक्रिय हैं और अभी पाकिस्तान सुपरलीग (पीएसएल) में खेलते हैं। वॉर्नर को सिडनी के पूर्वी उपनगर में शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये मामला ईस्टर संडे की रात का है। वॉर्नर अपनी वैन से वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में सिडनी पुलिस की जांच में टेस्टिंग' के लिए एक चेकपॉइंट बनाया हुआ था। पुलिस ने देखा कि चेकपॉइंट से कुछ ही दूरी पहले एक वैन अचानक रुक गई और पार्क होने लगी। पुलिस ने संदेह होने पर रोककर उनकी जांच की जिसमें पाया गया कि उन्होंने शराब पी है।

'द मास्टर्स' गोल्फ; 92 साल पुराने टूर्नामेंट में रोचक परंपराएं

मोबाइल बैन इसलिए फील्ड पर लैंडलाइन, विजेता तय करता है डिनर का मेन्यू

ऑगस्टा। गोल्फ की दुनिया में 'द मास्टर्स' का स्थान चारों मेजर टूर्नामेंट में सबसे ऊपर माना जाता है। इस साल प्रतिष्ठित मेजर चैम्पियन?शिप का 90वां संस्करण खेला जा रहा है। ऑगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब के हरे-भरे और शानदार मैदानों पर यह केवल एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि परंपराओं और इतिहास का महाकुंभ है।

मास्टर्स टूर्नामेंट की स्थापना वर्ष 1934 में गोल्फ के दिग्गज एमेच्योर चैम्पियन बॉबी जोन्स और निवेश बैंकर क्लिफर्ड रॉबर्ट्स ने की थी। मैदान के इतिहास (एक पूर्व नर्सरी) का सम्मान करते हुए, कोर्स के हर होल का नाम किसी न किसी पेड़ या झाड़ी के नाम पर रखा गया है।

मास्टर्स की सबसे बड़ी पहचान 'ग्रीन जैकेट' की शुरुआत 1937 में हुई थी। शुरुआत में इसे क्लब के सदस्यों के लिए पेश किया गया था ताकि वे अलग दिख सकें, लेकिन बाद में इसे विजेताओं को दिया जाने लगा।

क्लिफर्ड रॉबर्ट्स द्वारा 1940 के दशक में शुरू की गई एक परंपरा के तहत, मास्टर्स में कैडी (खिलाड़ी का बैग उठाने वाले) हमेशा सफेद जंपसूट (ओवरऑल) और हरी टोपी पहनते हैं। ड्वाइट आइजनहावर ऑगस्टा नेशनल के सदस्य बनने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। उनके लिए केबिन बनाया गया था, जिसकी डिजाइन में सीक्रेट सर्विस की भी भूमिका थी।

टूर्नामेंट का सबसे कड़ा नियम यह है कि मैदान पर सेल फोन या मोबाइल उपकरणों पर प्रतिबंध है। यदि कोई फोन के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है और उस पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मोबाइल न होने की भरपाई के लिए, पूरे कोर्स में पुराने जमाने के काले लैंडलाइन फोन लगाए गए हैं, जहां से मुफ्त कॉल कर सकते हैं। प्रवेश के लिए आवश्यक आधिकारिक टिकट को 'बैज' कहा जाता है। ये बैज इतने मूल्यवान होते हैं कि लोग इन्हें पीढ़ियों तक सहेज कर रखते हैं। बैज पाने का तरीका 'मास्टर्स लॉटरी' है। हर साल अनुमानित रूप से 20 लाख से अधिक लोग इसके लिए आवेदन करते हैं और जीतने की संभावना 1त्न से भी कम होती है।

ट्रॉफी रूम में मास्टर्स चैम्पियन जीत की रात क्लब के सदस्यों के साथ डिनर करता है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मंगलवार को एक विशेष डिनर आयोजित किया जाता है। इसमें केवल मास्टर्स विजेताओं (वर्तमान में 35 जीवित हैं) को आमंत्रित किया जाता है। डिनर का मेन्यू पिछले साल का विजेता तय करता है। मास्टर्स जीतने वाले खिलाड़ी को इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आजीवन निमंत्रण मिलता है। मास्टर्स में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए मर्सिडीज-बेंज कार दी जाती है।

ऑटोग्राफ का भी खास नियम; कोर्स की सूखी जगह पर हरे रंग से पेंट

यदि किसी फैन ने मास्टर्स के लोगो वाले झंडे पर ऑटोग्राफ मांगा है, तो एक दिलचस्प नियम लागू होता है। जिन खिलाड़ियों ने मास्टर्स जीता है, वे झंडे पर बने अमेरिका के नक्शे के अंदर हस्ताक्षर करते हैं, जबकि अन्य खिलाड़ियों को नक्शे के बाहर हस्ताक्षर करने होते हैं। मैदान को टीवी पर बिल्कुल परफेक्ट और हरा-भरा दिखाने के लिए कोर्स पर किसी भी सूखे या खाली स्थान को हरे रंग से पेंट कर दिया जाता है। विजेता ट्रॉफी चांदी के 900 टुकड़े जोड़कर बनाई है।

आईपीएल में आज होगी आरसीबी और रॉयल्स में टक्कर

शाम 7:30 से होगा मुकाबला

गुवहाटी। आईपीएल में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से होगा। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच में रॉयल्स टीम को घरेलू मैदान होने का लाभ मिलेगा। रियान पराग की कप्तानी में रॉयल्स ने अब तक अपने तीन मैच जीते हैं और इस समय 6 अंक के साथ ही वह अंक तालिका में शीर्ष पर है। वहीं रजत पाटीदार की कप्तानी में उतरी आरसीबी ने दो मैच जीते हैं जिससे उसके चार अंक हैं और वह तालिका में तीसरे नंबर पर है।

राजस्थान ने जहां चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटन्स और मुंबई इंडियंस को हराया है। वहीं आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स को पराजित किया है। दोनो ही टीमों के बल्लेबाज और गेंदबाजों ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में ये मुकाबला कांटे का होना तय है। दोनो की ही बल्लेबाज मजूबत है। राजस्थान के पास यशस्वी जायस्वाल और वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज हैं वहीं आरसीबी के पास विराट कोहली और रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी में हालांकि रॉयल्स ज्यादा मजबूत नजर आती है।

इस मैच में दोनो ही टीमें जीत दर्ज कर अपना हौंसला बढ़ना चाहेंगी।

दोनो ही टीमों की संभावित अंतिम ग्यारह

आरसीबी: रजत पाटीदार (कप्तान), फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, करुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और जैकब डफी।

राजस्थान रॉयल्स: रियान पराग (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा।

आरसीबी के पास जैकब डफी और भुवनेश्वर कुमार जबकि रॉयल्स के पास जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर जैसे तेज गेंदबाज हैं।

एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया

दिल्ली। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में, आयुष शेट्टी ने ची यू जेन को सीधे सेटो में 21-16, 21-12 से हराकर पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि, एचएस प्रणॉय चीन के वेंग हांग यांग से 12-21, 19-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इस बीच, महिला सिंगल्स में, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी.वी. सिंधु चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त वांग झीयी से 16-21, 15-21 से हार गई। मिक्स्ड डब्ल्स में ध्रुव कपिला और तनीशा क्रास्टो को भी मलेशिया के चेन तांग जी और तोह ई वेई से 13-21, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा।

सच का सामना करने से डरे बाबर आजम: कोहली से तुलना के सवाल पर पत्रकार से ही भिड़े

क्या था वो सवाल जिस पर बिफरे बाबर

मैच के बाद एक पत्रकार ने बाबर से कोहली की तुलना करते हुए प्रश्न किया। पत्रकार का कहना था कि भारत के पूर्व कप्तान लगातार मैच खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। पत्रकार ने बाबर से कहा कि वह कोहली की तरह मैच फिनिश नहीं कर पाते हैं, इस पर क्या कहेंगे। पत्रकार ने सवाल किया, विराट कोहली के शॉट्स की रेंज आपसे मिलती-जुलती है, लेकिन वो लगातार मैच को फिनिश करते हैं जो कि लोग कहते हैं कि आपमें इसकी कमी है। चूंकि कई लोग आपकी तुलना उनसे करते हैं तो इस तुलना पर आपके क्या विचार हैं?

कोहली के साथ तुलना को खत्म करने कहा

बाबर पत्रकार के इस सवाल से चिढ़ गए और उन्होंने कोहली के साथ तुलना को दृढ़ता से खारिज कर दिया। बाबर ने पत्रकार से ऐसी तुलना बंद करने को कहा और जोर देकर कहा कि यह एक गलत धारणा है कि उन्होंने मैच फिनिश नहीं किए हैं। बाबर ने कहा, चलिए

इसे यहीं खत्म करते हैं। ऐसे विचार अपने तक ही रखें। तुलना करना बंद करें और आगे बढ़ें। यह आपकी गलतफहमी है कि मैंने मैच फिनिश नहीं किए हैं। आंकड़ों में कोहली बाबर से काफी आगे बाबर की बल्लेबाजी, स्ट्रोकप्ले और पारी को संभालने की क्षमता के कारण वर्षों से उनकी तुलना कोहली से की जाती रही है। 2021 में यह तुलना तब और बढ़ने लगी जब बाबर ने आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 वनडे बल्लेबाज के रूप में कोहली के 1258 दिनों के दबदबे को खत्म किया और 2023 में वे मात्र 97 पारियों में 5000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। हालांकि, आंकड़ों में कोहली बाबर आजम से काफी आगे हैं और दोनों बल्लेबाजों में कोई तुलना ही नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट प्रशंसक हर बार बाबर की तुलना कोहली से करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है।

बार्सिलोना में यूईएफए चैम्पियंस लीग फुटबॉल में खेलते हुए एफसी बार्सिलोना और एटलटको डि मैड्रिड के खिलाड़ी।

4 गोल्ड, 2 सल्वर समेत 10 मेडल जीते; जरीन-लवलीना के नाम ब्रॉन्ज

एशयन बॉक्सिंग चैंपयनशप में भारतीय महला टीम टॉप पर

मंगोलया। मंगोलया में हुए एशयन बॉक्सिंग चैंप?यनशप 2026 में भारतीय महला टीम ने टॉप कया। टीम ने 4 गोल्ड, 2 सल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 10 मेडल जीते। टीम की हर खलाड़ी मेडल जीतकर लौटी। कोच सैंटयागो नवा की अगुआई में मीनाक्षी (48द्यद), प्रीत (54kg), प्रया (60kg) और अरुंधत (70केजी) ने गोल्ड जीते।

57 केजी के फाइनल में जैसमीन

57 केजी फाइनल में भारत को झटका लगा। जैसमीन लांबोरया को थाईलैंड की पुनरावी रूएनरोस ने 5-0 से हराया। अल्फया पठान (80+केजी) ने सल्वर मेडल जीता, लेकन फाइनल में कजाकस्तान की दीना इस्लामबेकोवा से 0-5 से हार गई। वह जैसमीन के साथ दूसरी भारतीय रहीं जन्हें सल्वर मला।

जरीन-लवलीना के नाम ब्रॉन्ज

इससे पहले हफ्ते में नकहत जरीन (54केजी), अंकुशता बोरों (65केजी), लवलीना बोरगोहेन (75केजी) और पूजा रानी (80केजी) ने सेमीफाइनल में हार के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कुछ वेट कैटेगरी में कम ख?लाडयों की वजह से लवलीना, पूजा और अल्फ?या को केवल भाग लेने पर ही मेडल म?ल गया। पुरुष वर्ग में व?श्वनाथ सुरेश (48केजी) और सचन सवाच (60केजी) शुक्रवार को अपने-अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगे।

मीनाक्षी ने पहले गोल्ड दलाया

मीनाक्षी ने मंगोलया की नोमुंदारी एन्ख-अमगालन को 5-0 से हराकर पहला गोल्ड दलाया। इसके बाद प्रीत ने चीनी ताइपे की तीन बार की वर्ल्ड चैंपयन हुआंग शयाओ-वेन को 5-0 से हराया।

प्रीत ने टोक्यो ओलंपक ब्रॉन्ज मेडलस्ट हुआंग के खलाफ दबदबा बनाए रखा। वहीं, प्रया घनघास ने नॉर्थ कोरया की वोन उन-ग्योंग को 3-0 से हराकर गोल्ड जीता।

अरुंधत चौधरी ने कजाकस्तान की बाकत सेइदीश को 4-1 से हराकर भारत के लए चौथा गोल्ड जीता। चारों भारतीय खिलाड़यों ने फाइनल जीतकर टॉप पोडयम हासल कया।

जिला पंचायत सीईओ ने विकास कार्यों का किया व्यापक निरीक्षण, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रेमालता पद्माकर द्वारा बीते शुक्रवार को जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर संचालित विकास कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत चारभाटा, पंडरभट्ठा, ढोलिया एवं झाल में चल रहे मनरेगा अंतर्गत तालाब गहरीकरण कार्य, डबरी निर्माण कार्य तथा आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्यों का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता एवं प्रगति की भी समीक्षा की गई। ग्राम पंचायत ढोलिया में स्थापित फीकल स्लज मैनेजमेंट (फाइकल स्लज मैनेजमेंट) प्लांट का भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने मौके पर उपस्थित ग्राम पंचायत सचिव एवं महिला स्व-सहायता समूहों को स्वच्छता बनाए रखने तथा प्लांट का नियमित एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बिटकौली में राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को राजस्व संबंधी कार्यों का गंभीरता एवं तत्परता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती पद्माकर ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर ग्रामीणों तक पहुंच सके।

निरीक्षण के दौरान स्थानीय स्तर पर चल रहे कार्यों की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने आवश्यक सुधारात्मक सुझाव भी दिए और बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया।

कांग्रेस संगठन में 'समाज का संतुलन' या 'समाज की अनदेखी'? ब्लॉक कार्यकारिणी में गांडा समाज को महज 1 पद!

सारंगढ़ /मूक पत्रिका

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा हाल ही में अपनी-अपनी कार्यकारिणी का गठन किया गया। बरमकेला, कोसीर, सरिया,सारंगढ़ शहर, सारंगढ़ ग्रामीण और बिलाईगढ़–इन सभी ब्लॉकों में नई टीमों की घोषणा के बाद अब सामाजिक संतुलन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं, वो चौंकाने वाले हैं। पूरे जिले के इन प्रमुख ब्लॉकों में मिलाकर गांडा समाज के केवल 6 लोगों को ही संगठन में स्थान दिया गया है, जबकि यह समाज क्षेत्र में अच्छी खासी जनसंख्या और राजनीतिक सक्रियता रखता है। सबसे ज्यादा चर्चा बरमकेला ब्लॉक को लेकर है, जहाँ गांडा समाज से केवल एक व्यक्ति को ही पद दिया गया। बाकी ब्लॉकों में भी स्थिति लगभग वैसी ही रही–कहीं एक, तो कहीं शून्य प्रतिनिधित्व! यह सवाल अब आम लोगों के बीच गूंजने लगा है– क्या कांग्रेस पार्टी का संगठन केवल कुछ चुनिंदा वर्गों तक सीमित रह गया है? क्या समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का दावा अब कागजों तक ही सिमट गया है? स्थानीय स्तर पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं में नाराजगी देखी जा रही है। शोसल मिडिया में भी इस नियुक्ति का विरोध वायरल हो रहा है,उनका कहना है कि चुनाव के समय हर समाज की बात होती है, लेकिन संगठन बनाते वक्त कुछ समाजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत होना है, तो हर समाज को उचित भागीदारी देना बेहद जरूरी है, वरना इसका असर आने वाले चुनावों में साफ दिखाई दे सकता है। अब देखना होगा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हैं– क्या कार्यकारिणी में संशोधन होगा? या फिर यह असंतोष धीरे-धीरे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे का रूप ले लेगा? फिलहाल एक बात तो साफ है– ÷प्रतिनिधित्व की राजनीति में संतुलन बिगड़ा, तो भरोसा भी डगमगाएगा!÷

सरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाईः स्विफ्ट डिजायर से 62 किलो से ज्यादा गांजा जब्त, तस्कर फरार..

सारंगढ़-बिलाईगढ़ /मूक पत्रिका

अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत सरिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उड़ीसा से गांजा लेकर आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार से पुलिस ने 62 किलो 245 ग्राम गांजा बरामद किया है।

हालांकि, कार्रवाई के दौरान कार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।

मुखबिर सूचना पर की गई घेराबंदी–पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार (ह्रष्ठ 02 क्चङ्क 7653) में गांजा लेकर कुछ लोग उड़ीसा से शक्ति-जांजगीर की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर ग्राम बोरिदा के बगीचा तालाब के पास मेन रोड पर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर चालक कार छोड़कर भाग निकला।

कार से 59 पैकेट में मिला गांजा–गवाहों की मौजूदगी में जब कार की तलाशी ली गई तो अंदर 59 पैकेट में कुल 62 किलो 245 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत करीब 5 लाख 90 हजार रुपये आंकी गई है, वहीं कार की कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है। कुल जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 10 लाख 90 हजार रुपये है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज–मामले में अज्ञात चालक के खिलाफ थाना सरिया में अपराध क्रमांक 71/2026 के तहत धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका–इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रमोद यादव के नेतृत्व में सउनि मोतीलाल डनसेना, विजय यादव, मोहन गुप्ता, विमल जांगड़े, खेमलाल, श्रवण टंडन, दिलीप स्नेही, दिगंबर, दिलीप साव सहित साइबर सेल के रामकुमार मानिकपुरी, दीपक मैत्री, कृष्णा डनसेना, मोतीलाल जांगड़े और थाना स्टाफकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बुदबुदा में राजस्व शिविर सम्पन्न, विभिन्न राजस्व प्रकरणों का हुआ निराकरण..

सारंगढ़-बिलाईगढ़ /मूक पत्रिका

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने दिशा निर्देश पर जिले में अप्रैल, मई और जून माह में राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी ग्राम पंचायतों में बारी बारी से राजस्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से की गई है। इसी कड़ी में 8 अप्रैल बुधवार को सरिया तहसील के ग्राम पंचायत बुदबुदा में शिविर का आयोजन किया गया था। जहां विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे राजस्व प्रकरणों का समाधान किया गया।

दोपहर तक मिले 6 आवेदन

हल्का नंबर 5 के पटवारी चूड़ामणि पटेल ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आज बुदबुदा में राजस्व शिविर लगाया गया है। इसके लिए कोटवार के माध्यम से एक दिन पहले ग्राम पंचायत के सभी गांवों में मुनादी कर जानकारी दी गई थी। इस शिविर में दोपहर की स्थिति यह कुल 6 आवेदन प्राप्त हुए है।

शिविर में सरपंच रही नदारत

आम जनता की सहूलियत के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया था मगर सबसे दिलचस्प बात यह रही कि दोपहर 3:30 बजे की स्थिति तक पंचायत की मुखिया यानी सरपंच ही इस शिविर में अनुपस्थित थी। इसके अलावा बुदबुदा के पंचगण ही शामिल हुए और आश्रित गांवों के पंच भी शिविर में खासी दिलचस्पी नहीं दिखाए। विभागीय अधिकारियों में पटवारी चूड़ामणि पटेल, पटवारी प्रह्लाद सिदार, पंचायत सचिव पंडित राम सिदार, कोटवार रामलाल चौहान शामिल रहे। बता दें कि 8 अप्रैल को जिले के सरिया तहसील के ग्राम पंचायत बुदबुदा, गोबरसिंहा, बरगांव, तोरा में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया था। जहां छोटे छोटे राजस्व प्रकरण, सीमांकन, अविवादित नामांतरण, बंटवारा, त्रुटि सुधार, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, ऋष्ण पुस्तिका आदि का निराकरण किया गया।

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक्कयन परीक्षा की सूचना जारी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक्कयन परीक्षा की सूचना जारी की गई है। इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट तथा एनडीए की तैयारी कराई जाती है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रयास आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं :- ऑनलाइन आवेदन/पंजीयन प्रारंभः 24 मार्च 2026ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथिः 17 अप्रैल 2026 (रात्रि 12 बजे तक)आवेदन पत्र में त्रुटि सुधारः 18 अप्रैल से 21 अप्रैल 2026 (रात्रि 12 बजे तक)जिला स्तर पर दस्तावेज परीक्षणः 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026प्रवेश पत्र डाउनलोडः 01 मई से 09 मई 2026प्राक्कयन परीक्षा की तिथिः 10 मई 2026 इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन https://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/Student-Admission-Detail लिंक के माध्यम से कर सकते हैं।

आवेदन से संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाइट तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय जिला बेमेतरा से भी प्राप्त की जा सकती है।

सुरेंद्र छाबड़ा की स्मृति में वी वाय हॉस्पिटल के सहयोग से बेमेतरा में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला मुख्यालय के महेश्वरी भवन में दिनांक 12 अप्रैल 2026 सुबह 10 बजे से स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार छाबड़ा की स्मृति में वी वाय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के विशेष सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर तथा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है इस शिविर में रायपुर के वी वाय मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सेवाएं बेमेतरा जिले वासियों एवं अंचल के आसपास के निवासियों को प्राप्त होगी इस आयोजन में डॉक्टर पूर्णेन्दु सक्सैना अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ सिद्धार्थ पाटनवार छाती रोग विभाग डॉक्टर योगेश विसनदासनी डॉक्टर सुलभ चंद्राकर हृदय रोग विभाग डॉक्टर एस एन पांडे डॉ विजय सेन जनरल फि जिशियन विभाग डॉक्टर के रवि राव चर्म रोग विभाग डॉ पीयूष प्रकाश सक्सेना कैंसर रोग विभाग डॉक्टर अंकित सहाय कैंसर रोग विभाग डॉक्टर अनुपमा जोशी नाक कान गला विभाग डॉक्टर सुबीर श्रीवास्तव जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी डॉक्टर सावेरी सरभाई सक्सेना स्त्री रोग विभाग डॉक्टर सौमित्र सिंह बाल एवं शिशु रोग विभाग डॉक्टर विक्रम सिंह फिजियोथैरेपी विभाग इन विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं दिनांक 12 अप्रैल 2026 सुबह 10:00 बजे से महेश्वरी भवन रेस्ट हाउस रोड बेमेतरा में उपलब्ध होगी साथ ही साथ ?3000 तक के पैथोलॉजी जांच निशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है यह शिविर हाल ही में दिवंगत स्व सुरेंद्र सिंह छाबड़ा जो लायंस क्लब के अध्यक्ष थे एवं बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के पिता थे के स्मृति में आयोजित किया जा रहा है जिसमें लोगों से अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर का लाभ उठाने की अपील छाबड़ा परिवार बेमेतरा एवं वी वाय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर की ओर से की गई है साथ ही साथ आम जनता से इस शिविर में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान की भी अपील की गई है जिससे मानव सेवा हो सके रक्त की एक-एक बूंद बहुत ही कीमती है समय पर जरूरतमंद को रक्त उपलब्ध कराया जा सके इसके लिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया है।

जगदलपुर में नशीली टेबलेट की बड़ी खेप बरामद, दो युवक गिरफ्तार

जगदलपुर /मूक पत्रिका

बस्तर पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली क्षेत्र में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 870 नग प्रतिबंधित अल्प्राजोलम नशीली टेबलेट तथा एक मोटरसाइकिल ष्टत्र 17 चङ्ग 6487 जप्त की गई है। बरामद टेबलेट की अनुमानित कीमत 4 लाख 35 हजार रुपये बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि दो युवक सन सिटी अटल आवास रोड के पास मोटरसाइकिल में नशीली टेबलेट बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में टीम गठित कर मौके पर घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध युवकों को पकड़कर पूछताछ की। आरोपियों ने अपना नाम आशीष जॉर्ज (23 वर्ष), निवासी कुम्हारपारा मां भवानी चौक, जगदलपुर तथा डीगेश्वर देवदास उर्फ शूटर (22 वर्ष), निवासी कुम्हारपारा, अब्दुल कलाम वार्ड 40, शंकर मंदिर गली, जगदलपुर बताया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 870 नग अल्प्राजोलम नशीली टेबलेट बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपी प्रतिबंधित दवाओं को रखने संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में उन्होंने बिक्री के उद्देश्य से टेबलेट रखना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 21(क्) हृष्ठक्कस् एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया।दोनों आरोपियों को 10 अप्रैल 2026 को न्यायिक रिमांड पर माननीय विशेष न्यायालय जगदलपुर में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौर, उपनिरीक्षक अरुण मरकाम, सहायक उपनिरीक्षक परिमल दास, प्रधान आरक्षक आनंद बघेल तथा आरक्षक बंसी लाल मौर्य, रंग लाल खरे, बलराम कश्यप और उत्तम ध्रुव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

चोरों के हौसले इतने बुलंद की खुलेआम दे रहे पुलिस को चुनौती

जैजैपुर क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियां,पुलिस के हाथ अब तक खाली

जैजैपुर/मूक पत्रिका

इन दिनों जैजैपुर थाना क्षेत्र में जगह जगह अवैध शराब,गांजा की बिक्री जोरों पर है साथ ही जैजैपुर थाना क्षेत्र में लगातार चोरियों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। पुलिस सक्रियता के दावे तो करती है, लेकिन लगातार चोरी की घटनाएं पुलिस प्रशासन की पोल खोल रही हैं। एक माह में चार बड़ी चोरी की वारदातों को चोर अंजाम दे चुके हैं लेकिन जैजैपुर पुलिस इन चार मामलों में एक का भी राजफाश करना तो दूर सुराग तक नहीं लगा सकी है।

पूरा मामला यह है कि 09 अप्रैल रात्रि में जैजैपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बहराडीह निवासी रामेश्वर चंद्रा पिता गजराज चंद्रा के घर रात्रि में घर के लोग सो रहे थे इसी बीच चोर घुसे और सन्दूक में रखे 15 तोला सोना, 85 तोला चांदी लगभग 38 लाख रुपये के जेवर एवं 60000रु नगद ले उड़े।तो वहीं जैजैपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुटराबोड़ में 20 मार्च की रात दो घरों में एक संतोष चंद्रा के घर से डेढ़ तोला हार, सोने की माला दो तोला,कान की आभूषण दो जोड़ा,चांदी तीन जोड़ा पैर पट्टी,चांदी का चैन, चांदी की तीन जोड़ा अंगूठी लगभग चार से पांच लाख के सोने चांदी के जेवर चोर लेकर रफूचक्कर हो गए,इसी गांव में बिहारी कर्ष के घर से 20 मार्च की रात सोने का फद्दक तीन,गुना सोने का चार,चांदी का चाबी छल्ला पांच,चांदी का एक जोड़ा पैर पट्टी,चांदी का तीन जोड़ा चूड़ा अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किया गया तो वहीं कुटराबोर की चोरी की घटना के एक हफ्ता पहले तुषार में दिनेश चंद्रा के घर भी लाखों के जेवर चोरी हुआ था लेकिन इन सभी चोरी घटनाओं में पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठी है। अभी तक किसी भी चोर तक पुलिस पहुंचने में नाकाम रही है। ऐसे में गृहमंत्री विजय शर्मा के बयान अगर किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो अपराधियों को बख्शा नही जाएगा। गृहमंत्री जी के इस बयानों का जैजैपुर थाना क्षेत्र में उल्टी गंगा बह रही है जहाँ चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती देते हुए लगातार जैजैपुर क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जा रहे हैं और जैजैपुर पुलिस अपनी औपचारिकता निभाकर अपनी जिम्मेदारियों से इति श्री कर ले रही है। जैजैपुर क्षेत्र के लोगों में लगातार हो रहे चोरी से डर और भय का माहौल बना हुआ है तो वहीं जैजैपुर पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी है।अब सबकी निगाहें जिले के पुलिस प्रशासन पर टिकी है यदि समय रहते इन चोरी की घटनाओं पर अंकुश नही लगेगा तो चोरी की घटना में वृद्धि होता रहेगा और पुलिस प्रशासन ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित। संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।